पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 4 अंक 44 | इंदौर, सोमवार 14 दिसम्बर से 20 दिसंबर 2009 | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 लोकतंत्र में मतदान सब झगड़ों की जड़

3 भ्रष्टाचार और लूट का आलम अपीलें रद्दी की टोकरी में

4 करोड़ों खर्च फिर भी खालवा में भूख से मौतें

5 इतने से वेतन में खुद को नहीं पाल सकते, परिवार तो दूर

6 मंदिरों की भूमि पर कालोनी शॉपिंग माल की तैयारी

7 सुरक्षा पर भारी पड़ेगा चीनियों का भारत प्रवेश

दिल्ली और देश की सत्ता चलती है वाशिंगटन से-2

कृत्रिम संकट- परमाणु बिजली में अरबों डकारने का

घरों से बड़े-बड़े उद्योगों, कृषि सब अमेरिका के इशारे व वसूली पर

भारत में पर्याप्त कोयला, जल, विद्युत, गैस आदि का पूर्ण व सही तरीके से दोहन तो भ्रष्टाचार, लूटखसोट की भेंट चढ़ चुका है। इसके विपरीत सूर्य ऊर्जा का असीम स्त्रोत होने के साथ पवन विद्युत का अभी सत्यता से 1% भी उपयोग नहीं कर सके हैं।

पूरे राष्ट्र में राज्यों के विद्युत मंडलों का कंपनियों में बदलने का आदेश भी वाशिंगटन का ही था ताकि डामोल जैसे अमेरिकी कंपनियां पूरे देश की बिजली पर अपना नियंत्रण, लूट, डकैती से् कमाई कर सकें। उन भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के उलूकों की चारा ंतरफ हर कंपनी में पूरे देश में बैठाने का आदेश भी विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक ने इसीलिए दिया थे कि भारतीय शासकीय उलूकों की फौज जहां बैठेगी पूरा चौपट कर देगी। अर्थात अब तो पूरे देश के विद्युत मंडलों की शाखाओं में विभक्त कंपनियों में हर साख पर उल्लू बैठा है। अंजामें भारत के गुलिस्ता को अंधेरे में रखने का षड्यंत्र इसीलिए रचा जा रहा है कि हर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के विश्व बैंक के ऋण से परमाणु बिजली घरों की स्थापना की जाए, जिसका यूरेनियम अमेरिका से आएगा जहां अमेरिकी और भारतीय अधिकारी सत्ता में बैठा हर गिद्ध अरबों रुपए कमीशन डकार सके। जानबूझकर इसलिए चलते हुए ताप विद्युत केंद्रों जो कोयलों से चलाए जा रहे थे उनकी चलती हुई इकाइयों को कभी कोयले की कमी बताकर, कभी इकाइयां पुरानी होने के नाम पर, कभी पानी की कमी या अन्य कारणों से जानबूझकर ठप्प किया जा रहा है।

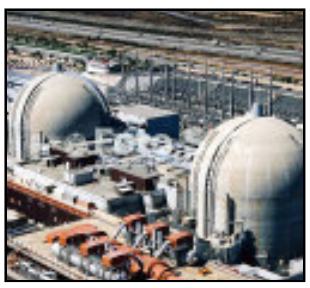

म.प्र. विद्युत मंडल के पुरानी संरचना को देखा जाए तो उसने सन 2000 में ही प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए सन् 2025 तक जल विद्युत केंद्रों की नियमानुसार समयावधि में ही अगर नियोजित संरचना के हिसाब से काम किया होता तो प्रदेश को जल विद्युत योजना से ही पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति घरेलू, व्यावसायिक, उद्योगों की, कृषि की आवश्यकताओं के अनुसार दस हजार मेगा वाट का उत्पादन मिल सकता था।

म.प्र. में सारणी, वीरसिंगपुर पाली, संजय गांधी, सतपुड़ा, जिनकी कुल क्षमता 3000 मेगावाट है किसी न किसी मे.वा. कारण से जानबूझकर बंद कर कम उत्पादन किया जा रहा है। बरगी रुपए 700 करोड़ की लागत से 1987 में बनाया गया था। 1994 तक उसके कुल उत्पादन से पूरी लागत वसूल कर ली गई थी। अब जबकि वर्तमान में पुनासा के इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर से प्राप्त बिजली को भी जानबूझकर अपने हिस्से की बिजली भी इसीलिए नहीं खरीदी जा रही ताकि जनता को कमी दिखाकर रुपए 250000 करोड़ परमाणु बिजली घर नरसिंगपुर के पास लगाया जा सके और रुपए 25 हजार करोड़ जो विश्व बैंक का ऋण दिया जाएगा बनते-बनते रुपए 40 से 50 हजार करोड़ की लागत आएगी 10% भी अगर **शेष पेज 2 पर**

विश्व बैंक ऋण बांटकर फैला रहा भ्रष्टाचार

अमेरिका जिम्मेदार है पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के लिए

पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन कभी भ्रष्टाचार कभी मानवाधिकार उल्लंघन, कभी शिशु मृत्यु दर, गरीबी, भूखमरी के नाम पर आर्थिक रूप से सम्पन्न तेल, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन जिसमें भी मुख्यतः एशियाई राष्ट्रों को ऊपर चाहे जब चाहे जैसे आरोप लगाकर बदनाम करने के पीछे उस धूर्त संकर प्रजाति के अमेरिका, उसके प्रशासन की साम्राज्यवादी नीतियों का पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें मानसिक, नैतिक रूप से वहां के प्रशासन, शासन को वहां की अर्थव्यवस्था को बदनाम कर वहां की जनता के दिलों में अपनी महानता, सहृदयता, दयालुता का रूपक दिखाकर मस्तिष्क में गहरी पैठ बनाना ही होता है, वर्तमान में स्थिति इस संदर्भ में ये है कि पूरे विश्व की कुल आबादी का समझदार और बुद्धिमान लोगों के दिलों में अपने आदर्श स्थापित करना होता है और कुल आबादी की 40% युवा पीढ़ी का विशेषतौर पर दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में 20% आबादी अमेरिका को आदर्श मानने के साथ इन सबके चलते स्वर्ग मानती है।

> अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के लिए ऋण देकर घी पीना सिखाता है

यही कारण है कि विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र व उसके संगठन अपना धन भी वहीं विनियोजित करता है, जहां उसको अपने धन के साथ अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत वहां के आर्थिक, प्राकृतिक स्त्रोतों को अपने कब्जे में लेना और अपने तरीके हांकना होता है। 77

१९९० का रूस का समयबाधित सुखोई एम.के.आई.

सुखोई स्क्वाड्रन जमीन पर

अच्छा है अभी देख परख लें वरना युद्ध में मुंह की खाएंगे

भारतीय वायुसेना का अहं हिस्सा माने जाने वाले सुखोई जो रूस की वायुसेना ने 1990 में ही समयबाधित करार दे कर बाहर कर दिए थे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने मोटे कमीशन पर रूस से खरीदकर रूस की गंभीर होती तात्कालीन अर्थ व्यवस्था को संभालने में भारी मदद की थी जब रूस की वायुसेना का समय बाधित लड़ाकू जहाज भारतीय वायुसेना का युद्ध में कितना साथ देगा,यह तो अपनी परीक्षण और नियमित अभ्यास उड़ानों में औंधें मुंह गिरकर अपनी वास्तविकता का परिचय दे रहा है। फिर हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, वायुसेना के एयर मार्शल बड़ी-बड़ी ढींगे हांक रहे हैं, विश्व की श्रेष्ठ वायुसेना सबसे लड़ने में सक्षम है शांतिकाल में यह हाल है तो युद्ध काल में कितनी सक्षम होगी, जबकि हमारे शत्रु वायुसेना और नई पीढ़ी के एफ-16 जैसे परमाणु हथियार ढोने में सक्षम, हवा से हवा में मिसाइलें दागनें में सक्षम, युद्धक विमानों से हमारा युद्ध होगा। हम तो 21वीं

सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो महंगाई काबू की जा सकती है

केंद्र सरकार सट्टोरियों के चंगुल में

जब गैर कानूनी है जुआ-सट्टा तो वस्तुओं का सट्टा वायदा क्यों?

केंद्र की कांग्रेस सरकार में बैठे गिद्धों का गिरोह, सत्ता में बैठकर अपनी कमाई, वसूली और कमीशन के लिए कानूनी, गैर कानूनी कुछ भी नहीं देखता, उसे कमाई से मतलब होता है, जनता अगर चीखती, चिल्लाती और आंसू बहाती है तो ये गिद्ध उन आंसुओं से भी कमाई का रास्ता खोज निकालते हैं। जैसे गिद्धों को प्रामियों की मौत और उससे प्राप्त भोजन का इंतजार रहता है। वैसे ही कांग्रेसियों को भी जनता के आंसुओं, भूख से होने वाली मौतों उस पर घड़ियाली आंसु बहाकर जनधन को लुटाने और लूटने का इंतजार रहता है।

पूरे भारत में महंगाई का एकमात्र कारण है वस्तुओं पर सट्टा और वायदा व्यापार, यदि सट्टा और वायदा व्यापार बंद कर दिया जाए तो सोने, चांदी से लेकर गेहूं, दाल, चावल और शक्कर की कीमतें जमीन पर आ जाएंगी, महंगाई आसानी से नियंत्रण की जा सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये कहना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हम महंगाई पर बढ़ती आम रोजमार्रा की आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगा सके तो हम पूछना चाहते हैं कि जब जुआ सट्टा खेलना और खिलाना कानूनी अपराध है या गैर कानूनी है तो वस्तुओं जिसमें गेहूं, दाल, चावल, शक्कर से लेकर सीमेंट, लोहा, सोना-चांदी आदि का सट्टा व्यापार क्यों और कैसे चल रहा है। यदि इन वस्तुओं पर सही व्यापार **शेष पेज 2 पर**

समयमाया की करप्शन की साइटें बंद होते ही

ओसामा, स्वाइन फ्लू के भूत विश्व मीडिया में

सन 2000 से समय माया द्वारा चलाई जा रही करप्शन इंडिया की साइटें जो याहू कॉम के ग्यासिटीज पर चल रही थीं बेशक वह मुफ्त साइट थी ने जब पैसे मांगने शुरू किए और 26/10/09 की आखरी तारीख निश्चित की और अर्थाभाव के कारण हर महीने धन चुकाना संभव नहीं हुआ तो ये साइटें बंद कर दी गई।

इसके पूर्व जब-जब ओसामा ने सिर उठाया तब-तब हमारी साइटों ने इसकी हकीकत साइटों के माध्यम से दुनिया में व्हाइट हाउस, सी.एन.एन बीबीसी से लेकर विश्वभर के न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों को भेज दी जाती थी। चूंकि ओसामा बिन लादेन लीवर केंसर से सितंबर 06 में ही मर चुका है। हाल ही में जुलाई 09 में भी उसे व्हाइट हाउस ने जिंदा करने की कोशिश की थी तो श्री अजमेरा ने यह सूचना अपनी साइटों पर -ओबामा ने ओसामा को हथियारों का बाजार और आतंकवाद का व्यवसाय गर्म करने के लिए पुनर्जीवित किया। जैसे ही लिखकर पहुंचायी तीसरे दिन से ही ओसामा बेचारा फिर कब्र में जाकर **शेष पेज 2 पर**

सम्पादकीय

लोकतंत्र में मतदान सब झगड़ों की जड़

लोकतंत्र में मिले जातन के मतदान का अधिकार ही सारे दंगे, फसादों, भ्रष्टाचार, आरक्षण की जड़ है धर्म, समाप्रदायिकता, जातिवाद, लिंगभेद, रंगभेद, आतंकवाद के पीछे बैठा होता है, जनता को रिझाने, डराने, धमकाने,खरीदने, शराब, शबाब, कबाब, रुआब, चुनावों के अहं हिस्सा माने जाते हैं। लोततंत्र की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जो ये सब शाम, दाम, दंड, भेद, चारो अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, सफल होकर सत्तासुंदरी का वरण करता है।

अब सब सुंदरियां स्वयं मैदान में हों तो वो अपनी सुंदरता, लटकों, झटकों के साथ अपना त्रियाचरित्र उपयोग कर चुनाव भले ही जीत जाए, परंतु उनकी अपुनी समझ लोभ लालच के लिए उन्हें जनता का हित तो दूर अपना भविष्य भी ढंग से नहीं देख पाती। माना कि अपवाद हर जगह होते हैं, पंरतु इनका प्रवेश ही वास्तविक समस्याओं से हटाने के लिए काफी होता है और अब जब वो बराबरी की हो जाएगी और बराबरी से बैठेगी, तो जनता की समस्याएं कम अपनी वास्तविक समस्याओं और धन बटोरने की आंकक्षा ज्यादा बलवती रहेगी, जिसके लिए वो तन रूपी हथियारका खुलकर उपयोग कर वास्तविकताओं पर ध्यान कम ही रहेगा, जनता का जहां तक सवाल है तो वो मरने के लिए पैदा हुई है। चाहे वो लोकतंत्र हो या राजतंत्र बस अंतर इतना सा होता है कि लोकतंत्र की आवाज येनकेन प्रकारेण और अंदर तक पहुंच जाती है और राजतंत्र में दरबारियों में गुम होकर रह जाती है।

ये मतदान ही तो था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर चौराहे पर खड़ा कर झगड़ों को आमंत्रण दिया गया है, अब झगड़ों की जड़ में पुरातन पंथी कारण जर, जोरू, जमीन में से जोरू सत्ता में भी आ खड़ी हो गई है। अब सत्ता ने युद्ध कमाई से चलकर लुगाई के लिए भी होंगे। फिर जहां तक प्रश्न नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, निगमों का है तो इंदौर नगरनिगम साक्षी है जब पार्षदों ने पार्षदों की सभा में महिला पार्षद को झगड़ा चलते वस्त्रहीन कर दिया था, बाद में निगम कर्मचारियों ने उसे अपने तन के वस्त्र खोलकर ढांका था। लोकतंत्र वैसे भी कभी वोटों के लिए चुने जाने के बाद नोटों के लिए वास्तविकता में नोंच तंत्र होता है। चाहे तो भारत की लोकसभा से लेकर पंचायतों की बात हो या अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विश्व के अन्य देशों की।

वोट कबाड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना कर मजबूरी में जनता भी वोट देकर भूल जाती है। जिन्हें सत्ता में पहुंचने के बाद ढंग से लिखना-पढ़ना भी नहीं आता जाता हो वहां वर्षों से बैठे धूर्त सचिव व अन्य कर्मचारी ऐसे प्रतिनिधियों को मोहरा बनाकर खुलकर भ्रष्टाचार कर धन डकारते हैं और इन्हें रबर की मुहर बनाकर उपयोग करते रहते हैं, जब भ्रष्टाचार की बात उठती है तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों के सिर मढ दिया जाता है। यह तथ्य पंचायतों से लेकर जनपदों, नगर पालिकाओं, निगमों राज्य की विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक का कटुसत्य है। वोटो की यही राजनीति वास्तविक विकास को पीछे भी धकेल रही है।

धीमा जहर विक्रेता किशोर, पाकीजा आतंकवादियों का सहयोगी

पेज 3 से जारी

अब वही किशोर वाधवानी हमारै नगर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनके खास सिपहसलार रमेश मेंदोला के साथ उनके खास सिपहसलार रमेश मेंदोला के साथ उनके गरबा आयोजनों में धन देकर उनका न केवल प्रायोजक बना वरन् सारे दैनिक समाचार पत्रों में आधे पूरे पन्नों के विज्ञापनों में भी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो छापे गए। जिसमें मुख्यमंत्री शिव चौहान भी था। बात भाजपा की हो तो हर राष्ट्र भक्त पाठक को चुभती ही है कि कैसे धीमा जहर बैचने वाले के साथ सिद्धांतोंका ढिंढोरा पीटने वाले अपने बड़े-बड़े फोटो छपवा कर धन्य हो रहे हैं।

हमारे राष्ट्र में अनादिकाल से राष्ट्रभक्ति, का सदा ही अभाव रहा है। आखिर हम तो ऐतिहासिक गुलामों की औलाद है। हमें राष्ट्र और राष्ट्र की जनता से क्या मतलब है। हमारे पेट, बैंक बैलेंस और घर भरना चाहिए। हम वो चंडाल है बुड्ढा मरे या जवान हमें तो वसूली से काम। गौरी बंधु देश द्रोही हैं। जिन पर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए वो शान से पुलिस प्रशासन से लेकर मीडिया जिस पर हर आंख के आँसू पोंछने की जिम्मेदारी है धन बांटने वालों की अंधभक्ति में जुटे हैं। फिर जिस भाजपा को राष्ट्रभक्तों की देशप्रेमियों की पार्टी माना जाता था वो भी शामिल हो गए। जनताको जहर बेचने वालों को पेरौल की सूची उनकी भुगतान सूची में आयकर, विक्रयकर, पत्रकार, सी.एम.ओ.,जिलाधीश, पुलिस, कांग्रेस तो थे ही भाजपा भी उसकी सूची में शामिल कर वह अब बड़े आसान तरीके से कोई जहर बेचेगा, कोई सिमी जैसे आतंकवादियों को धन उपलब्ध करवाएगा।

कोई गरबा कर यौवन रस चूसने के लिए धन दे रहे है तो कोई बड़ी-बड़ी धर्म सभाएं करवा कर अपनी यश-कीर्ति ऐसे दो नम्बर के पैसे से प्राप्त कर रहा है। आखिर तुलसीदास ने सैकड़ों वर्ष पहले ही लिखा है- समरथ को नहीं दोष गुंसाई। अर्थात् पैसे होगा तो सब दुम हिलाएंगे। धर्म, कानून, मंत्री, अधिकारी, जनता, जनता को बर्बाद कीजिए या देश को, हम सब घोर स्वार्थी है।

ओसामा और...

पेज 1 से जारी

चैन से सो गया था, पर साइटें बंद होते ही विश्व के टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार पत्रों से पुनः कब्र से निकलकर आतंकवाद के रंगमंच पर अवतरित हो तांडव के लिए तैयार किया जा रहा है।

आश्चर्य तो इस बात का है, विश्व का मीडिया जिसमें टीवी न्यूज चैनलस् के साथ सीएनएन, बीबीसी बेशक दोनों ही अमेरिकी षड्यंत्रों के शासकीय प्रसार माध्यम है। उस भूत तो जगाकर अमेरिकी बाजार को गर्म करने को षड्यंत्रकारी है, के साथ विश्व के समाचार पत्र भी इस समाचार को पूरी तन्मयता से प्रकाशित कर रहे हैं। पूरे दक्षिण एशिया में पुनः भय का वातावरण बना रहे हैं। वैसे भी अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी भय के व्यवसाय की ही खा रहे हैं। जिसमें विश्व के प्रचार माध्यम आग में घी झोंककर लपटों से तपिश पैदा करने में जुटे हैं।

वही हाल स्वाइन फ्लू का भी हुआ, स्वाइन फ्लू भी एड्स की तरह केवल अमेरिकी दवाई बेचने वालों का शिगूफा है। स्वाइन फ्लू अमेरिकी दवा कंपनियों का दहशत का फ्लू है। उन्होंने दवाइयां बनाई तो उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच विश्व स्वास्थ्य संगटन उसका बाजार गर्म करने पर तुल जाता है, दुनियाभर के मीडिया के माध्यम से दहशत पैदा कर अपनी दवाइयां, कंडोम, वैक्सीन बेचता है। जैसे हेपेटाइटिस ए से लेकर जेड तक के टीके, एचआईवी (एड्स) से नाम पर पांच पैसे का कंडोम 5 रुपए में वह भी मुफ्त में मिले कंडोम्स की नई पैकिंग कर बाजार में बेचता है। एड्स के नाम पर कुल मिलाकर महिलाओं का गर्भ ठहरने के भय से मुक्तकर खुली वैश्यावृत्ति करवाने का ही षड्यंत्र है। वैसे ही स्वाइन फ्लू के बुखार के नाम 25-50 पैसे की बुखार की गोलियां को रु. 25-50 में बेचने का षड्यंत्र है। अमेरिकी दवाएं बिकीं उनका व्यवसाय हुआ वह भी हेपेटाइटिस के टीके की तरह गायब हो जाएगा।

हमारी साइटें इन सब षडयंत्रों का राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई के साथ विवरण देकर पर्दाफाश करती रही है। जिससे अमेरिकी और उसके गुलाम मनमोहन प्रधानमंत्री और उनकी अम्मा मिलकर इसदेश में दहशत का वातावरण फैलाकर एक तरफ जनता का ध्यान वास्तविकताओं अर्थात महंगाई से हटाकर बीमारी की दहशत में उलझा देते हैं। तो दहशत के वातावरण की आड़ लेकर अरबों रु. की निरर्थक दवाइयों का कचरा खरीदकर खुद भी मोटा कमीशन खाते हैं और अपने अमेरिकी आकाओं को भी खुश करते हैं। शीघ्र ही हमारी साइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट समयमाया डॉट कॉम पर हम राष्ट्र को और विश्व की जनता को सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगे।

सुखोई...

पेज 1 से जारी

शताब्दी में भी 1960 और 1970 के दशक के मिग -21, 23, 29 उड़ा रहे हैं जो कि रूसी वायुसेना ने 1970 में ही बाहर कर दिए थे। जो हाल रूसी युद्धक विमानों मिग-21 से 29 तक की सीरिज के जहाजों का हुआ, वही इन रूसी सुखोई एम.के.आई. का हो रहा है।

हमारा हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल, लि. जिसे स्वयं वायुसेना, रक्षा मंत्रालय सफेद हाथी मानता है कैसे और क्या रखरखाव हो रहा है ये आसमान से टपकते युद्धक विमान बता रहे हैं। फिर हमारी भारत सरकार में बैठे हर धूर्त की आदत है, जो विदेशों में समयबाधित या बेकार हो जाता है हम उसी गंदगी को चाटने, झाड़ने, पोंछने और चमकाकर इठलाने के आदि है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए जाने वाले पायलेट्स मरें या जिंदा रहे इनकी बला से, जबकि दूसरी तरफ हमारी वायुसेना लड़ाकू जहाज चालकों की कमी से वर्षों से परेशान है, वह भी इनकी बला से ये तो परमाणु समझौता कर मोटा कमीशन डकार परमाणु बिजली घर लगाने को बेताब हैं। जबकि शत्रु हर पल हर क्षण सीमाओं पर हरकतें कर युद्धोन्मादी हो रहा है, वह भी हमारी कुल सीमाओं के अधिकांश क्षेत्रों पर कच्छ का खाड़ी से पाकिस्तान आजाद कश्मीर तक और उसी आजाद कश्मीर से अरुणाचल, मिजोरम तक वो 24 घंटो युद्धोन्मादी हरकत करते रहा है। फिर कांग्रेसी हरामखोर अय्याश और कमीशन खोरों को इसकी बिलकुल चिंता नहीं है। इन्हें तो केवल खोखली झूठी आधारहीन मुखमैथुनी घोषणाएं करने और बयानबाजी करने का कह दो टीवी चैनल और पत्रकारों के सामने।

केंद्र सरकार...

पेज १ से जारी

जो राष्ट्रीय वस्तु और डेरोवेटिव्स विनियम केंद्र पर अरबों रुपए रोज का सट्टा एनसी डेक्स में जिसकी शाखाएं न केवल हर शहर में वरन गांवों की मंडियों में भी या तो खोली जा चुकी है या इन कृषि उपज मंड़ियों को ऐसे सट्टे के कृषि उपजों के वर्तमान और भविष्य के वायदा, सौदों का अड्डा बना कर न केवल व्यापारियों वरन किसानों उत्पादकों को भी इस मकड़जाल में उलझाया जा रहा है, ताकि भविष्य में बाजार भावों में कमी आने या मंदी आने की दशा में रोने के अतिरिक्त कोई चारा न बचे। अभी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सट्टा व्यापार को बढ़ाने में लगी है और इनका मकड़जाल तहसीलों की मंडियों तक में फैला कर इन कृषि फसल उत्पादकों, किसानों को इस मकड़जाल में वायदा व्यापार की आदत डाली जा रही है जैसे ही सब के आदी हो जाएंगे तो आसानी से जालसाज गिरोह बाज इन किसानों का माल और पैसा उलझाकर दिवालिया घोषित हो जाएंगे या भाग जाएंगे। मंदी में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां धन इधर-उधर अंतरित कर सट्टे में हानि के नाम पर हाथ ऊंचे कर देंगी, तो फिर हजारों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अभी तत्काल में किसी का समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका में पिछले दो वर्षों में 120 बड़े बैंक दिवालिया हो सकते हैं तो भारत में बड़ी-बड़ी कंपनियां दिवालिया क्यों नहीं हो सकती है।

सट्टा जहां वस्तुओं की वास्तविक खरीद-फरोख्त तो दूर सटोरियों ने माल की शक्लो-सूरत या छूकर भी नहीं देखा होता है। बस भविष्य के वायदों पर बेचने खरीदने के सौदे होते हैं। उन सटोरियों के इस सौदेबाजी का सीधा असर आम उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक बाजार और उसके उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। सत्ता में बैठा प्रधानमंत्री मनमोहन और कृषि मंत्री शरद पंवार चूंकि इस सौदेबाजी का सीधे बड़े सटोरियों से धन डकार रहे हैं तो ये जालसाज शूकर इसके कारण बढ़ी महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए तो मीडिया को टीवी और मुद्रित प्रसार माध्यमों पर तो ढोंग दिखाते हुए दिखेंगे , दिखाएंगे पर सट्टा व्यापार बंद नहीं कर रहे हैं।

इस सट्टे का मूल उद्देश्य है कि भारत के बाजार में बैठे छोटे व्यापारी इस सट्टे के माध्यम से ज्यादा लंबी खरीदी न कर सके और विदेशों की, देश की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अरबों रुपए का माल खरीदकर अच्छा माल विदेशों का निर्यात कर दे और मोटा माल कमाए जब देश की जनता त्राहि-त्राहि करने लगे तो कमी का रोना रोकर वहां का सड़ा कचरे का माल, कचरे के भाव खरीद कर भारत में दुगुने से लेकर 10-20-50 गुना दरों पर खरीदी दिखाकर ये दानव वाणिज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कृषि मंत्री के साथ दानवों का सरदार मनमोहन भी अरबों रुपए का कमीशन डकार सके जैसा कि पिछले तीन-चार वर्षों से गेहूं, शक्कर, चावल, खाद्य तेलों, दालों, फलो, मसालों आदि में किया जाकर ये सफेदपोश डकैतों का समूह मोटा कमीशन डकार रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो इस सट्टे का व्यापार पर पूर्ण रोक लगाकर महंगाई का चारों खाने चित्त कर सकता है।

सट्टे के इस व्यापार से अमीर जो अरबपति है वो खरबपति होंगे तो लखपति शीघ्र ही इस सट्टे में पूंजी गंवाकर खाक हो जाएंगे। जिन किसानों को ये अभी वर्तमान में लाभ का सौदा दिख रहा है। लंबे समय में बीटी कपास की सट्टा फसलों की तरह कर्ज में लदे होकर आत्महत्याओं की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सटोरियो की अपनी कमाई से मतलब है, उसे उत्पादक, जनता, देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इससे गरीबी रेखा से ऊपर से लेकर निम्न मध्यमवर्गीय और आम मध्यमवर्गीय बढ़ती महंगाई और सट्टे से बुरी तरह से पिसा रहा हैं और वहीं सदा से पिसता आया है और पिसता रहेगा, क्योंकि नौकरीपेशा की महंगाई की तुलना में न तो वेतन बढ़ेगा और न अन्य कमाई, इसके विपरीत उसकी आय का आधे से ज्यादा दो वक्त के अपने और परिवार के भोजन में ही खर्च हो जाएगा, फिर बाजार की तुलना में शिक्षा, बिजली, पानी कर, संचार, किराया व अन्य सेवाओं की तुलना में बढ़ेगी और बढ़ रही है। इन जालसाज, धूर्त कांग्रेसी गिरोह को इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी कमीशनखोरी वसूली से बढ़ी महंगाई से जनता जितना रोएगी चिल्लाएगी ये राक्षस गिरोह उतना खुश होता है और जनता आंसुओं से भी इन्हीं की कमाई के स्त्रोत बन जाते हैं।

कृत्रिम संकट...

पेज १ से जारी

तात्कालिक सत्ता में बैठी भाजपा या कांग्रेस को मिले को रुपए 2500 से 4000 करोड़ तक किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री जिसके पास परमाणु विद्युत है आसानी से डकारेगा, वहीं प्रदेश के अधिकारियों को भी सत्ता में बैठे मंत्रियों को भी 10%-5% डकारने में भी हजारों करोड़ का लेनदेन होगा। इस कर्ज को आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी नहीं भुगतान कर सकी ब्याज और ऋण की किस्त तो कोई भी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसका प्रभार सौंपकर गुलामों पर राज करने और वसूली करने का सीधा अवसर हाथ आ जाएगा। यही हाल राष्ट्र के सभी बड़े प्रदेशों यथा, उ.प्र., राज., बिहार, आंध्रप्रदेश के साथ 27 राज्यों में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना से सत्ताधीशों को हजारों करोड़ का बैठे ठाले कमीशन प्राप्त हो सकेगा।

हमारे म.प्र. को क्या जरूरत है परमाणु बिजली घर की मात्र मोटा कमीशन के कारण अन्यथा हमारे प्रदेश में पर्याप्त कोयला है, नर्मदा के ऊपर 4 बड़े बांध बन चुके हैं। महेश्वर अधर में है। आसानी से 10 हजार मेगावाट की आपूर्ति तो प्रदेश को ही मिल सकती है। इसके विपरीत सत्ता में बैठे भूखे गिद्धों जिसमें प्रशासकीय इंडियन एव्यूसिंग सर्विस व चुने हुए विधायक, नेता, मंत्री सभी को धन चाहिए। चाहे वो राष्ट्र या प्रदेश के प्राकृतिक सम्पदाओं, जनहितों को गिरवी करके मिले या बेचकर इन्हें वसूली और लूट से काम जो हाल म.प्र. का है वही देश के सभी 27 देशों और 7 केंद्र शासित राज्यों का जानबूझकर कमी पैदा की जा रही है, कमी न होने के बाद बी कृत्रिम संकट पैदा कर जो भूमिका बनाई जा रही है तो मात्र परमाणु बिजली घरों के लिए।

यह तो मात्र परमाणु बिजली घरों से बिजली बनाने के बाद निकले रेडियो धर्मी कचरे को कैसे नष्ट किया जाएगा जो 1200 वर्षों से लेकर 3000 वर्षों तक अपनी रेडियो धर्मिता नहीं खोता। शायद इन हरामखोरों का उससे कोई मतलब नहीं। उस टनों से निकलने वाले कचरे से कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं जो कुछ ही घंटों में पूरे देश की धरती को जो अभी काला, पीला, हरा, सफेद, कृषि उपजों के रूप में सोना उगलती है। सैकड़ों वर्षों के लिए बंजर बना दिया जा सकता है जिसका ये स्वार्थ के अंधे, भूखे गिद्ध अंदाज नहीं लगाना चाहते।

महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमिका में जिन परमाणुवीय व नाभिकीय आयुधों का उपयोग किया गया था उसका सहस्त्रों वर्ष बाद भी असर समाप्त नहीं हुआ है, वह कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी बंजर है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां परमाणु आयुधो का उस काल में प्रयोग किया गया जहां अभी भी हरियाली का तिनका भी पैदा नहीं होता, फिर रूस के चेरनोबिल के परमाणु बिजली घर से पानी रिसने की घटना ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। उसका असर रूस के केचेरमनोबिल के आसपास देखा जा सकता है। अमेरिका इस प्रकार परमाणु संयंत्र बेचकर लाखों-करोड़ों डालर कमाऐगा कृत्रिम विद्युत संट भी उसी के इशारे पर पैदा किया जा रहा है क्या भारतीय सत्ताधीश गुलामों को समझ नहीं आ रहा।

यही कमाई और कमीशन मुख्य का करण था अमेरिका के साथ परमाणु समझौते जिसके इस राक्षस मनमोहन प्रधानमंत्री ने पूरी सत्ता को भी दाव पर लगाने से नहीं चुका था। उसमें हजार करोड़ का मिलने वाला कमीशन के लिए जनता और मीडिया से झूठ बोलकर समझौता किया गया।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. सूचना आयोग जालसाजों का अड्डा

भ्रष्टाचार और लूट का आलम अपीलें रद्दी की टोकरी में

धूर्त शूकरों की फौज वसूली कर वर्षों सुनवाई नहीं करती

म.प्र. सूचना आयोग में बैठे तीनों धूर्त मुख्य सूचना आयुक्त पी.पी. तिवारी, सू.आ. इकबाल अहमद, दोनों सेवानिवृत्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी, तीसरा इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस का दिनेश जुगरान जिन्होंने जिंदगीभर शासकीय सेवा में रहकर लूट पाट मचाई और भ्रष्टाचार का तांडव किया। इन हरामखोर धूर्तों से ये उम्मीद करना किये न्याय करेंगे और वो भी सूचना के अधिकार में, जिन श्वानों को भ्रष्टाचार की हड्डियां चाटने का चस्का लगा हो वो 60वर्ष की उम्र में सुधरेंगे ये कभी नहीं सुधरेंगे। दूसरा जिन धूर्तों ने इन्हें बैठाया है चाहे वो शिवराज मुख्यमंत्री हो या इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का प्रदेश का मुख्य सचिव राकेश साहनी इन हरामखोर भ्रष्टों ने इसीलिए इस शर्त पर बैठाया है कि वो शासन के खिलाफ नहीं जाएंगे। आखिर रोटी बंगला, कार, नौकर चाकर सारी सुविधाएं इन सेवानिवृत्त गिद्धों को इसीलिए दी गई है कि वो शासन के हितों का ख्याल रखेंगे। जनता, आवेदक जिन के दम से शासन चला रहा है। जाए भाड़ में कानूना बनाया है तो इसका मतलब तो कदापि नहीं कि शासन या प्रशासन की सारी सच्चाइयां सामने रखकर उसकी धज्जियां उड़वा दें।

ये आयोग के हरामखोरों के अगर हाथ से भी पत्र दो, तो 40 से 45 दिन बाद उसे पंजीबद्ध करते हैं। जबकि 30 दिन में अपीलों की सुनवाई हो जानी चाहिए। ये हरामखोर साल से दो वर्ष तक उसे अलमारियों में सजा कर अगरबत्ती दिखाते हैं, जब तक अपीलें हाथ में हैं, जब तक ही कमाई होगी, निराकरण होते ही खेल खत्म।

श्री अजमेरा ने पचासों अपीलें फाइल कर रखी है। जिसमें सबसे ज्यादा अपीलें वाणिज्य कर इंदौर के विरुद्ध की है। चूंकि उन भ्रष्टों से मोटा लेनदेन कर लिया गया है, वर्षों गुजर जाने के बाद भी उन अपीलों का पता नहीं है, जबकि उसके बाद की अपीलों पर जिनमें इनका लेनदेन नहीं होता है, उनकी सुनवाई कर ली जाती है, इन हरामखोरों को फिर सुनवाई में इंदौर क्षेत्र के आयुक्त इकबाल अहमद के चेले निजी सचिव सक्सेना उसे पहले अपने कक्ष में ले जाकर लेनदेन की गुटर-गूं करता है, अगर सौदा पक्का तो धूर्त इकबाल अहमद फिर कानूनों की लुगदी बनाकर आवेदक को पेट कर अपनी फैसले पर हस्ताक्षर करवा लेता है।

इन हरामखोरों की फौज से पूछो कि इन शूकरों ने पिछले 3 वर्ष के इतिहास में कितनों पर रुपए 250 रुपए प्रतिदिन का दंड आरोपित किया। आवेदक ने आने-जाने, समय बर्बाद करने और क्षतिपूर्ति के लिए कितनों को क्षतिपूर्ति दिलवायी।

हाल ही इनकी धूर्तता, मक्कारी का नमूना देखिए कि इन्होंने 30 नवम्बर 09 को एक अपील के लिए पेशी पर बुलाया पर दूसरे दिन दूसरी अपील के लिए 1/12/09 को फिर पेशी पर बुलाया, इन्हें सूचना आयुक्त क्या बना दिया ये भ्रष्टाचार की गंदगी चाटने वाले हरामखोर आवेदकों को ही आर्थिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगते, ये चाहते तो दोनों पेशी एक ही दिन करके दोनों अपीलें सुन सकते थे। कानून इनकी बपौती है जैसे चाहेंगे ये आवेदक को परेशान करेंगे और अनावेदकों से दोनों हाथ वसूली करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये कैसे अनावेदकों को परेशान कर कम से कम सूचना प्राप्त करने के आवेदन लगवाने की कोशिस कर रहे हैं। उन्हें कैसे-कैसे परेशान करने का राष्ट्र स्तर पर आयाम स्थापित कर हम वसूली में व्यस्त हैं।

इन हरामखोर जालसाजों की म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे पत्र में जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इन्होंने अधिकार विहीन बनाना का जो प्रयास किया था ताकि ये शूकरों की फौज हर आवेदक को जिसे प्रथम अपील में समुचित न्यायोचित निराकरण नहीं मिले तो वो दूसरी अपील में जाए इन्हें अनावदेको के साथ ही प्रथम अपीलीय अकिरियों को विभाग के ही होते हैं, सामान्यतः नोंचने-खसोटनें का पर्याप्त अवसर मिले, इसीलिए ये किया कि इन जालसाजों के आयोग में अधिकतम द्वितीय अपीलें पहुंचे।

जब तथ्य समय माया ने प्रकाशित कर दिए तो मु.सु.आ. बौखला कर प्रेस में बयान जारी किया कि हमारे यहां से पत्रकारों ये दस्तावेज चुरा लिए हैं। जबकि ये फोटो कापी एक अपीलीय स्तर के अधिकारी ने इंदौर में ही उपलब्ध करवा दी थी, इन्होंने यह जानने के लिए देवास जिलाधीश को पत्र लिखकर हर विभाग से आवेदनों की कपीयां और प्राप्त आवेदनों की पंजी की प्रतियां मंगवाई थीं।

म.प्र. सूचना आयोग कितना ईमानदार है उसका पता तो आयोग की कार्यशैली से लग ही जाता है। दूसरा इन हरामखोरों से पूछो कि पूरे प्रदेश में धारा 4 के पालन में इन्होंने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, सन 2005 से अभी तक कितने पत्र लिखे। तीसरा आयोग की अपनी बेवसाइट पर प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों के कितनी जानकारियां डाली, म.प्र. सूचना आयोग की स्वयं की साइट ने धारा 4 का पालन अभी तक क्यों नहीं किया। चौथा इनके दिए हुए अपीलों के आदेशों का पालन कितनों ने किया, यदि नहीं किया तो इन शूकरों ने अभी तक क्या किया। देवास जिलाधीश के खिलाफ 14/4/08 के आदेश में अभी तक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, आर.टी.ओ. ने अगस्त 08 के आदेश में परिपालन में अभी तक कुछ नहीं किया। ये क्या कर पाए न ही उन पर दंडारोपण ही किया न ही अभी तक किसी आवेदक को उसकी क्षतिका ये श्वानों की फौज भुगतान करवा पाई।

इनको अपनी वसूली और नोंच खसोट से फुर्सत मिले तो ये बेचारे आवेदकों की सुनें।

केंद्रीय विधि विभाग को चाहिए कि इन देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयोगों पर भी अंकेक्षण और निगरानी समिति गठित कर इनकी अचानक छापा मार कार्यवाही कर जांच कर इन शूकरों का निलंबन और हटाने की कार्यवाही की व्यवस्था करें।

बस पैसा हो, कैसा भी हो

मंत्री, मीडिया, धर्म-कानून सब हिलाते हैं दुम

भारत में आदमी के पास पैसा हो कैसा भी हो, उसके सामने धर्म, कानून, भाजपा, कांग्रेस सब उसके सामने दुम हिलाते हैं।यह बात दिल्ली से लेकर देश के सभी शहरों, कस्बों पर लागू होती है। चाहे फिर वह कानून के विरुद्ध धीमा जाहर बेचकर ही क्यों न खिला रहा हो, सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहा हो, उसकी सच्चाइयों,वास्तविकता की जानकर भी सरकारी अधिकारी, निरीक्षकों से लेकर मीडिया के टुकड़खोर श्वान भी दुम हिलाते नजर आते हैं। छोटे-मोटे साप्ताहिकों, जिनके पास धेले की अक्ल नहीं होती, पढ़े लिखे होते नहीं कानून की एबीसीडी तो दूर कलम पकड़ना न जानने वालों के लिए ये माफिया न केवल भगवान होते हैं, वरन ऐसे माफिया के छोटे-मोटे पत्रकारों से लेकर दैनिक वालों को भी बड़े-बड़े विज्ञापन देकर पत्रकारों को मोटा मासिक चंदा देकर खरीद लेते हैं। स्वाभाविक है ये मीडिया के मुखेंरे श्वान चाहे तो भास्कर हो, हिन्दुस्तान टाइम्स हो, जैसे भी उनकी पार्टियों में जाकर उन्हें न केवल उपकृत करते हैं, वरन उसे भी वो अपना सौभाग्य मानते हैं।

जिलाधीश एस.पी. जैसे ऊंचे पदों पर विराजे अधिकारी भी मीडिया को देख हाथ पैर ठंडे कर लेते हैं। ये हाल मुकेश, अनिल अंबानी,. टाटा बिरला, भारती के सुनील मित्तल से लेकर इंदौर का ही किशोर वाधवानी जैसे धीमा जहर बेचने वाले सारे शिमला गुटका वाला, पाकीजा शोरूम के मालिक गौरी बंधी जो सिमी को वित्तीय सहायता देता था, आखिर भास्कर की घुड़कियोंसे बचा ही लिया गया, जबकि ये देश कीजनता इंदौर की जनता को लूटकर देश के खिलाफ ही कर रहे हैं। मीडिया, मंत्री, अधिकारी सब बचाने आगे आएं।

शिमला गुटका के मालिक किशोर वाधवानी जो न केवल आयकर की करोड़ों की हर वर्ष चोरी करता है। वाणिज्यकर की चोरी करता है। अपने गुटकों में कत्थे के नाम पर विशुद्ध मैग्नेशियम कार्बोनेट को खुल कर वर्षों से मिला रहा है। खाद्य अपमिश्रण अधि. 1954 की धारा 44 (जे) में स्पष्ट है कि किसी भी उत्पाद में तम्बाखू नहीं मिलाई जाएगी, इसके विपरीत उसके अधिकांश उत्पादों में तम्बाखू मिलाई जा रही है। पूरे बाजार में तम्बाखू के पाउचों से पान की दुकानें भरी पड़ी हैं। इसके विपरीत न केवल खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण विभाग के नौ के नौ ही खाद्य निरीक्षक हरामखोर महीना वसूली कर न केवल वो सब वरन खाद्य एवं औषधि नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव भी महीना वसूली कर चुप बैठा है फिर वही क्यों आयकर, विक्रय या वाणिज्य कर अधिकारियोंसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिलाधीश सब ही हरामखोर महीना डकार कर चुप बैठ रहते हैं।ये तो सरकारी मुखेंरे श्वानोंकी ओर मीडिया के श्वानों की छोटीसी कहानी है।

यदि हम भाजपा के नेताओं को ही लें लें तो कल तक किशोर वाधवानी मोटा चंदा देकर कांग्रेस के टिकट की जोड़-तोड़ में लगा रहा था, यह बात इंदौर के ही सारे दैनिक में थी। **शेष पेज 2 पर**

म.प्र. राज्य सूचना आयोग जालसाजों का अड्डा

कार्य देवास जिलाधीश का, श्रेय चाहिए आयोग को

धारा ४ की जानकारी श्री अजमेरा की अपील पर जिलाधीश ने डलवाई

* धारा 4 की जानकारी इंटरनेट साइटों पर डालने का सबसे ज्यादा लाभ शासन व शासकीय अधिकारियों को ही।

* सूचना के अधिकार में 50% से ज्यादा आवेदनों पर कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं होगी।

* 50% आवेदनों का जवाब 1 लाईन में ही हल हो जाएगा।

* सूचना आयोग 4वर्ष बाद भी धारा 4 की जानकारी नहीं चाहता इंटरनेट पर।

* प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहे तो 100% अपीलों का न केवल निराकरण वरन् दोषियों पर दंड आरोपित कर सकता है।

* जो अधिकार सूचना आयोग को वही अधिकार कानून में प्रथम अपीलीय अधिकारी को।

* सूचना आयोग को हजम नहीं हो रहा, देवास के जिलाधीश श्री सचिन सिन्हा द्वारा 4 की जानकारी सभी विभागों की इंटरनेट पर डालना।

* धारा 4 की जानकारी इंटरनेट पर डालने से आयोग में भ्रष्ट धूर्तों मु.सू. आयुक्त पी.पी. तिवारी, सू. आयुक्त इकबाल अहमद और सू.आयुक्त. दिनेश जुगरान का रुतबा घट जाएगा। आयोग में द्वितीय अपीलें पहुंचना कम होंगी तो इनकी कमाई और धमकाने चमकाने का कारोबार खत्म हो जाएगा।

* श्री अजमेरा की प्रथम अपील के निराकरण में जिसमें धारा 4 की जानकारियां ही मांगी गई थीं और 4 के 17 बिन्दुओं की जानकारी डालने का आग्रह किया गया था जिस पर न केवल ध्यान दिया गया, वरन जिलाधीश ने हर विभाग के जिलाधिकारी की इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए हर बैठक में लगातार खिंचाई भी की। परिणाम 4 माह में ही सामने आया।वर्तमान में स्थिति में 20-25 विभागों की 17 बिन्दुओं की जानकारी देवास जिले की साइटों पर है। अर्थात श्री सिन्हा और श्री रावत जो जिलाधीश कार्यालय के लोकसूचंना अधिकारी है ने लगातार प्रयासों से इस कार्य को सम्पन्न करवाया और निरंतर प्रयास में न केवल जिले, सभी विभागों से जो अभी तक जानकारी संग्रहित नहीं कर पाए हैं कार्य को पूरा करने के लिए कह रहे हैं।

* जब आधे से ज्यादा कार्य सम्पन्न हो चुका है या हो रहा है, जिसकी भनक सूचना आयोग को लगी तो उसने एक पत्र क्रमांक रा.सू.आ./ विविध/ 2009/22/2217 भोपाल दिनांक 11/11/09 मात्र जिलाधीश देवास को भेजकर जानकारी मांगी जिसमें दो प्रपत्र भी संलग्न किए गए सूचना के अधिकार में जिलाधीश देवास से प्राप्त किए गए, प्रस्तुत है-

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन द्वितीय तल,
58, अरेरा हिल्स भोपाल
क्रं./रासूआ/विविध/2009/12217 भोपाल दि.11/11/2009
प्रति,
कलेक्टर
जिला देवास
मध्यप्रदेश

विषयः जिलों में स्थित समस्त लोक प्राधकारियों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने वाले आवेदन एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त होने वाली प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण एवं 17 बिन्दु के मैन्युअल की जानकारी विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके जिले में आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों के कार्यालयों अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण की जानकारी से मा. मुख्य सूचना आयुक्त महोदय अवगत होना चाहते हैं।

अतएव आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 'अ' एवं 'ब' अनुसार विभागवार/ कार्यालयवार जानकारी दिनांक 01/01/09 से दिनांक 30/09/09 तक की स्थिति में पत्र प्राप्ति के 21 दिवस के भीतर राज्य सूचना आयोग, भोपाल को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में उपलब्ध समस्त लोकप्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 04 के अंतर्गत 17 बिन्दु के मैन्युयल बाबत जानकारी कि यह मैन्युयल तैयार किए हैं अथवा नहीं, की जानकारी भी भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार
(पराग करकरे)
अवर सचिव
राज्य सूचना आयोग

*सूचना आयोग की प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिकारहीन सिद्ध बनाने का पूर्व केप्रयास के विरुद्ध जब समयमाया ने छाप दिया तो सूचना आयोग के मु.सू. आई. आ.पी. तिवारी को ये बहुत नागवार गुजरा और इस बात को लेकर ये बयान जारी किया कि पत्रकारों ने उनके कार्यालय से पत्र चुरा लिए हैं, जबकि उक्त सामान्य प्रशासन के माध्यमसे जारी पत्र की प्रतियां पूरेप्रदेश में जारी की गई थी। हर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम से जिसकी प्रति एक अधिकारी श्री अजमेरा को स्वयं ही दिखाई थी जिसकी सूचना के अधिकार में प्रति प्राप्त कर ली गई थी। जब उसकी व्याख्या करके छाप दिया गया तो इन्हें अपने कुकर्मों की सच्चाई से बौखलाहट उत्पन्न हुई।

* इस पत्र के माध्यम से सूचना आयोग यह जानना चाहता है कि आखिर ये पत्र किसने और क्यों दे दिया, क्या देवास के कार्यालयों से ये पत्र अजमेरा को हाथ लगा।

* यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिकार ही नहीं अपील निराकरण का तो सूचना अधिकार अधि. 05 में उसकी व्यवस्था ही क्यों की गई। इसीलिए कि अपील का निराकरण प्राथमिक स्तर पर ही हो जाए। और आवेदक को राहत 4मिल सके पर सूचना आयोग **शेष पेज 7 पर**

महिला बाल विकास में भ्रष्टाचार और लूट का तांडव

करोड़ों खर्च फिर भी खालवा में भूख से मौतें

धूर्तों अधिकांश योजनाओं को कागजों में पूरा कर हर डकारते हैं करोड़ों

खंडवा।

शासन गरीब महिलाओं और उनके बच्चों के लिए करोड़ों रुपए हर वर्ष देता है। इसके विपरीत खंडवा जिले में भूख से मौतें होती रही है, वर्तमान की स्थिति भी अगर विभाग में बैठे डकैत ऐसे ही सारी कागजी खानापूर्ति करते रहेंगे और सारे पैसे पर डाका डालकर हजम करेंगे तो गरीब गर्भवती और गरीब महिलाओं और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मरते रहेंगे। वैसे खंडवा जिले से महाभ्रष्ट, अय्याश जालसाज मंत्री विजय शाह फिर मंत्री मंडल में आ गए हैं, स्वाभाविक है कि सारे जिले के अधिकारी और कर्मचारी उसकी मर्जी से भारी भ्रष्टों को ही बैठाया गया है। जिलाधीश एसबी सिंग के भ्रष्टाचारों की कहानी समयमाया पहले भी छाप चुका है। फिर इंदौर में जिलाधीश रहते हुए कम गुल नहीं खिलाए। अभी सन 2007 से भी इस जालसाज मंत्री विजय शाह के इशारों पर न केवल भ्रष्टाचार चारों तरफ किया जा रहा है, इन्हीं के समय खालवा विकासखंड में करोड़ों रुपए महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास में खर्च कर दिया गया, इसके विपरीत कुपोषण से मौतें नहीं रुकीं।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त खंडवा महिला बाल विकास में आवंटन और खर्च का विश्लेषण प्रस्तुत है जो कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक केप्रशासनिक अधिकारी समझ सकें वैसे तो ये इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के धूर्तों और जालसाजों की सरपरस्ती में ही पोषित पल्लवित हो रहा है। भ्रष्टाचार जालसाजियां फिर भी इन हरामखोरों को आईना दिखाना आवश्यक है।

सन 2007-08 में पूरक पोषण आहार के नाम पर रुपए 4 करोड़ 4 लाख 35 हजार 500 आबंटित हुआ, खर्च रुपए 3 करोड़ 65 लाख 38 हजार 889 खर्च इसमें से 60% अर्थात रुपए 2 करोड़ हजम कर लिया गया जो बालवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर एकीकृत महिला बाल विकास अधिकारी विकासखंड से लेकर जिला अधिकारी तक डकारा गया।

क्र. 2 मंगल दिवस रुपए 26 लाख 22 हजार में से रुपए 25 लाख 37 हजार इसका 60% अर्थात रुपए 15 लाख हजम, अति गरीब गर्भवती महिला व प्रसव पूर्व सहायता योजना रुपए 3,37 हजार में से रुपए 2 लाख से रुपए 1 लाख 20 हजार महिला जागृति शिविर प्रशिक्षिण कार्यक्रम में रुपए 2,68 हजार पूरा खर्च रुपए 2 लाख हजम झूठे व्हाउचर लगाए 80% अनुदान रुपए 748 हजार आवंटन में से रुपए 199 हजार खर्च रुपए 1 लाख हजम।

सन् 2008-09 में पूरक पोषण आहार रुपए 70 लाख आवंटन रुपए 701 लाख खर्च रुपए 4 करोड़ हजम, वास्तविक खर्च 20 से 40% ही होता है। 60 से 75% तक नीच से ऊपर तक झूठे व्हाउचरों से हजम हो जाता है। सरकारी अधिकारियों से लेकर बालवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना में रुपए 169 लाख रुपए 1 करोड़ हजम।

वर्ष 09-10 में पूरक पोषण आहार योजना में रुपए 836 लाख स्वीकृत, 25/10/08 तक रुपए 505 लाख खर्च अर्थात रुपए 3 करोड़ हजम, लाड़ली लक्ष्मी योजना में रुपए 5 करोड़ 13 लाख 48353 स्वीकृत 25/10/08 रुपए 66 लाख 59 हजार खर्च में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा रुपए 30 लाख तक हजम 31/3/10 तक ये सारा पैसा भी झूठे व्हाउचरों के सहारे कागजी जमा खर्च कर हजम कर लिया जाएगा। आदिवासी खालवा विकासखंड जिसकी कुल आबादी 200 की जनगणना के अनुसार 1 लाख 60 हजार सबसे ज्यादा कुपोषण और भूख और बीमारियों से मौतें इसी विकासखंड में होती रही, चूंकि दूरदराज का क्षेत्र होने के कारण यहां पर अधिकारी और कर्मचारी अधिकांशतः गायब ही पाए जाते हैं, तो यहां की जनपद और पंचायतों में यह राशि चाहे वो महिला बाल विकास की हो या ग्रामीण विकास की कागजों पर ही खर्च कर ली जाती है। सबसे ज्यादा नरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

म.प्र. के प्रधान व महालेखाकार के अंकेक्षण की टिप्पणियों में जो कि मात्र कागजी श्वानों की फौज होती है, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप अंकेक्षकों ने स्वयं भी भ्रष्टाचार के धन में अपना हिस्सा डकार कर नहीं लगाए और छोटी-छोटी खानापूर्ति कर अंकेक्षण पूराकर लिया।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग खंडवा (म.प्र.) के अवधि 04/07 से 11/08 तक के लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-एक

(क) प्रस्तावना

(1) सामान्य

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के माह 4/07 से 4/08 तक की अवधि के लेखाओं के नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय प्रदान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम म.प्र. ग्वालियर के स्थानीय लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 5.5.08 से 16.5.08 तक सम्पन्न की गई।

कार्यालय के अभिलेखों के पूर्व लेखा परीक्षा माह 11.8.05 से 3.7.07 तक की अवधि दिनांक 16.4.07 से 25.4.07 तक सम्पन्न की गई थी।

निम्नांकित अधिकारियों ने लेखा परीक्षा अवधि में उनके सम्मुख दर्शायी अवधि से कार्यालय प्रमुख के पद पर पदभार संभाला। जो कि वितरण, आहरण अधिकारी थे।

(2) आंतरिक लेखा परीक्षण एवं पर्यवेक्षण-

(क) वित्तीय नियमों का अनुपालन तथा अभिलेखों का रख-रखाव।

मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग एक के उपनियम 291 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने कार्यालय के अभिलेखों की माह के अंत में जांच कर अनियमितताओं एवं उनमें सुधार के प्रयत्नों का विवरण सहित सामान्य प्रतिवेदन नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। लेकिन उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है।

(ख) आंतरिक लेखा परीक्षा

(1) लेखा परीक्षा की आवर्ति अवधि में कार्यालय के लेखाओं की विभागीय लेखा परीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की गई है।

(2) लेखा परीक्षा की आवृत्ति अवधि में कार्यालय के लेखा की लेखा परीक्षा संचालक कोष एवं लेखा विभाग के दल द्वारा नहीं की गई है।

(3) लेखा परीक्षा अवधि के अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया।

(ग) पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की लम्बित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार थी-

भाग दो (क)

गंभीर वित्तीय अनियमितताएं

निरंक

अन्य अनियमितताएं

कंडिका-1 पूरक पोषण आहार मद में आंगनवाड़ी केंद्रों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना राशि रु. 83.67 लाख।

म.प्र. में दिनांक 1.4.2007 से नवीन पोषण आहार नीति लागू की गई। जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के अलग-अलग प्रकार के खाद्यान्न लोकल फूड का प्रदाय किया जाता है।

म.प्र. शासन महिला बाल विकास भोपाल के पत्र क्रमांक एफ.-03/21/2007/50-2 दिनांक 11.5.07में दिए गए निर्देशों के अनुसार-

(1) आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त वातों में इस नीति के अनुसार खाद्यान्न हेतु अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है जो 2 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगा।

(2) कार्यकर्ता द्वारा रोकड़बही लिखी जाएगी। प्रतिमाह हुए व्यय हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करोगे। परि. अधि. द्वारा एक उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर जिला कार्यालय को जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधि. जिला कलेक्टर की स्वीकृति के आधार पर उतनी ही राशि उनके खातों में जमा करेंगे। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 में पोषण आहार मद में जो राशियां जमा कराई गई थीं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी प्राप्त नहीं हुए थे। राशि रुपए 83.87 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र पात्रत होना शेष थे।

(राशि लाख में)

जिला जमा	संचा. जमा	योग	व्यय	शेष
358.16	98.59	454.75	371.08	83.67

वर्ष 2007-08 में कुल राशि रुपए 454.75 लाख जमा कराई गई थी जिसके विरुद्ध 371.08 लाख व्यय की गई। शे्ष राशि रु. 63.67 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त थे। (3/08)

विभाग ने उत्तर में बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त बैंक खातों में राशि अग्रिम में जमा कराई गई है जिसका उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को भेजे जाएंगे।

कंडिका-2 ग्राम्य योजनांतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय चलाने हेतु प्रवायऋणों की वसूली न होना रुपए 4.32 लाख।

ग्राम्य योजनांतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वयह का व्यवसाय चलाने हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है जिससे ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके। ग्राम्य योजना महाप्रबंधक म.प्र. महिला वित्त विकास निगम भोपाल के निर्देशानुसार 11 नवम्बर 1991 से चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत खंडवा जिले के परियोजना क्षेत्र/ विकासखंड में प्रत्येक वर्ष में चयनित ग्रामीण महिलाओं को 500-500 रुपए के मान से ऋण राशि स्वीकृत कर प्रदाय की गई।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खंडवा जिले के परियोजना क्षेत्र में विकासखंड की ग्रामीण महिलाओं को वर्ष 1991-92 से 2007-08 तक की अवधि में राशि रुपए 7,66,000.00 के ऋण स्वीकृत किए ए थे। ऋण के विरुद्ध वसूली की राशि रुपए 3,34,437.00 थी। बकाया राशि रुपए 4.31,553 वसूली हेतु शेष थी।

उत्तर में बताया गया कि यह योजना वर्ष 1992 से 2005 तक जिले में संचालित रही है। ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है। अधिकांश हितग्राही जीवित नहीं है और स्थान छोड़कर चले गए है। अतः ऋण राशि को अपलेखित (write of) करने की कार्यवाही भोपाल स्तर से की जा रही है। प्रस्ताव भेजे गए हैं। विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ऋण प्रदायकर्ता द्वारा वसूली हेतु समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रतिवर्ष वसूली योग्य राशि बढ़ती रही।

कंडिका-3 वाणिज्यिक कर/वैट का राशि चालान द्वारा जमा न कर सीधे प्रवायकर्ता को भुगतान करना रुपए 0.62 लाख।

म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत यदि किसी प्रदायकर्ता फर्म को रुपए 5000/- या इससे अधिक का भुगतान करते हैं तो वाणिज्यिक कर की कसौटी स्त्रोत पर ही करके राशि चालान द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को जमा करना है। यदि कटौती न कर पूरे बिल का भुगतान किया जा रहा है तो वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 34 एवं 35 का उल्लंघन है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी खंडवा द्वारा वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित फर्मों से सामग्री क्रय की गई थी। इन फर्मों को भुगतान करने से पूर्व वैट की राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा नहीं की गई। बल्कि पूरा भुगतान प्रदायकर्ता को कर दिया गया।

फर्म का नाम- 1. मैं. विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज खंडवा, बिल क्र./दि. 6/05.29.5.07 राशि- 64.230, वैट राशि- 9359 फर्नीचर क्रय

2. मै. विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज खंडवा-बिल क्र./दि. 6/9/.07/19.7.07 राशि- 49,227, वैट राशि- 5470 फर्नीचर क्रय

3. मै. साईनाथ मेटल इण्डस्ट्रीज इंदौर- बिल क्र./दि. 075/20.9.07 राशि- 4,10,509, वैट राशि- 15,788 बर्तनक्रय

4. मै. जय इण्टरप्राइसेस शिवपुरा-बिल क्र./दि. 167/7.12.07 राशि-8,12,591, वैट राशि- 31,253 बर्तन क्रय

यद्यपि उपरोक्त सभी क्रय लघु उद्योग निगम के माध्यमसे किए गए थे, लेकिन भुगतान करने में वाणिज्यिक कर अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संबंधित फर्मों से वैट टेक्स जमा किए जाने के बारे में पत्र लिखा जाएगा तथा उनसे वैट टैक्स जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं क्योंकि भुगतान करने समय नियमों का पालन नहीं किया गया।

कंडिका-4 बाल संजीवनी अभियान योजना की समीक्षा।

(आवंटित राशि का व्यय हितग्राहियों पर नहीं होना रुपए. 1.14 लाख)

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक डी.डी.ओ./बजट/2007-08/2428 दिनांक 25.3.08 के अनुसार जिला जिला कार्यक्रम अधिकारी म.वा.लि. खंडवा को मोविलिटी सपोर्ट/बाल संजीवनी अभियान योजना में राशि रुपए 1.14 लाख का आवंटन वर्ष 2007-08 के लिए उपलब्ध कराया गया था। संचालनालय के निर्देश थे कि आवंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 07-08 मेंशतप्रतिशत किया जाए और यदि राशि की आवश्यकता नहीं हो तो राशि तत्काल समर्पित की जाए।

कार्यालयीन अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी खंडवा के द्वारा उक्त राशि का आहरण बिल क्र. 189 दि. 27.3.08 के द्वारा किया गया। तथा आहरित राशि को निम्नानुसार परियोजनाओं को वितरीत किया गया-

क्र.	परियोजना	राशि
1.	खंडवा	13000
2.	हरसूद	13000
3.	वालडी	13000
4.	पुनासा	13000
5.	छैगांव माखन	13000
6.	पंधाना	13000
7.	खंडवा (ग्रा.)	13000
8.	खंडवा (श.)	13000
9.	जिला कार्या.में	10000
	कुल	114000

परियोजनाओं को दी गई राशियों का उपयोग बाल संजीवनी अभियान योजना के अंतर्गत अभी तक नहीं किया गया है। (4/2008) राशि संबंधित परियोजना अधिकारियों के बैंक खातों में जमा है। संचालनालय के निर्देशों के अनुसार (आवंटित राशि का उपयोग वर्ष 2007-08 में ही करना था।)

लेकिन नहीं किया गया इस प्रकार बाल संजीवनी अभियान योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन का उपयोग वर्ष 2007-08 में प्राप्त हितग्राहियों के लाभार्थ नहीं किया गया।

विभाग ने उत्तर में बताया कि योजना के तहत हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष पर चलता रहता है। प्राप्त राशि को व्यय हेतु संबंधित परियोजना अधिकारियों को अग्रिम दिया गया है। जिला स्तर पर राशि रुपए 10.000.00 का उपयोग किया गया।

रोकड बही के अनुसार जिला स्तर पर भी राशि रुप. 10,000/- का उपयोग पी.ओ.एल. पर अभी तक नहीं किया गया है। और न ही परियोजना अधिकारियों द्वारा राशि को व्यय किया गया है।

भाग-दो (ग)

नमूना जांच टिप्पणी जारी करना-

लेख परीक्षा में पाई गई लघु अनियमितताओं का समावेश नमूना जांच टिप्पणी में किया गया है, जिसे पृथक से जारी किया जा रहा है। कृपया नमूना जांच टिप्पणी का पालन प्रतिवेदन सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (निरीक्षण सिविल-11) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) म.प्र. ग्वालियर को प्रस्तुत करें। नमूना जांच टिप्पणी में उल्लेखित बिन्दुओं का अनुपालन उच्च अधिकारियों के निरीक्षण एवं कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा के समय सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

पूरक नमूना जांच टिप्पणी

कंडिका-1

शिशु एवं बाल पोषण योजना का सफल क्रियान्वयन न होना व्यय राशि रुपए 0.43 लाख। संचालनाय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के बजट आवंटन पत्र क्रमांक म.वा.वि./डीडीओ बजट/2007-08/2287 भोपाल दि. 17.3.20087 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी खंडवा को शिशु बाल पोषण योजना के अंतर्गत जिले में सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण हेतु राशि रुपए 42.900.00 का आवंटन प्रदाय किया गया था। स्वीकृति आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे-

(1) वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करें।

(2) म.प्र. कोष संहिता वित्त संहिता एवं संचालनालय के निर्देशों का पालन करें।

(3) सुनिश्चित करें कि प्राप्त आवंटन का उपयोग इसी वित्त वर्ष में हो ताकि शत प्रतिशत राशि का उपयोग सुनिश्चित है।

(4) अनियमित आहरण न करें राशि की आवश्यकता न हो **शेष पेज 7 पर**

साप्ताहिक समय माया

वेतन रुपए २५००/- में ढाई हजार परेशानियां

इतने से वेतन में खुद को नहीं पाल सकते, परिवार तो दूर

वेतन मजदूरों से कम, जिम्मेदारी देश के भविष्य की

भोपाल। संविदा शिक्षकों को वर्षों से रुपए 2500/- के वेतन में गांवों में नौनीहालों के जो राष्ट्र का भविष्य है जिम्मेदारी उन्हें शिक्षा देने और उनके भविष्य संवारने की है। वर्तमान म दैनिक मजदूरी करने वालों, अशिक्षिति श्रमिकों की मजदूरी भी रुपए 100 प्रतिदिन से ज्यादा है। साथ ही संनिर्माण कामगारों के लिए शासन की बहुत सी योजनाएं भी हैं। जिनमें उनकी दुर्घटना के फलस्वरूप चिकित्सा, मृत्यु होने पर रुपए 50000/- देने तक का प्रावधान है, परंतु संविदा शिक्षकों को वर्षों से वेतन तो रुपए 2500/- दिया जा रहा है जहां वो नौकरी करने गांवों में जाते हैं, उनको वहांरहने की व्यवस्था में झोपड़ियां भी किराए से नहीं मिलती स्वाभाविक है ये स्नातक स्तर का शिक्षक या तो बस का महीने का पास बनवाकर सायकिल से या वाहन से आने जाने का खर्च भी इसी रुपए 2500 में कैसे वहन करतेहोंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसके विपरीत उसे मध्याह्न भोजन के नाम पर लकड़ी कंडों की व्यवस्था से लेकर गैस लगाने, घर मैं भले ही खाना न बनाया या बनाना भी आता हो,उन्हें वहां बच्चों को भोजन करवाना है। वह भी रुपए दो में दाल रुपए 90-95 कि.की. एक सब्जी और कम से कम 4 रोटी हर बच्चे को खिलाना है। फिर सरपंच को पंचों से लेकर गांव के हर दबंग आदमीको भी इन बेचारों को झेलना ह। गांवों में न तो सब्जी मिलती है न गैस वह भी उसे व्यवस्था करना है, किसी के खेत से लानाहै न ही तो जहां से वो आनाजाना करता है वहां से सस्ती से सस्ती सब्जी ढूंढनाहै। गांवों में बैठे सरपंचों, सचिवों से लेकर उसको जिलाधिकारी, पंचायत, निरीक्षक, विकासखंड, शिक्षा निरीक्षक, विकासखंड अधिकारियों, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलाधीश, उसके प्रतिनिधि इन सबकी डांट फटकार सुनना है। अगर स्कूल में 250 बच्चे हैं तो शिक्षक-पालक संघ, फिर 250 बच्चों के माता-पिताओं को कभी मां तो कभी पिता अर्थात 750 को उनको भी झेलना है, जबकि गाहे बगाहे छोटे-मोटे देहाती तो थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हैं और समाचार पत्रोंको बांटते हैं वो सारे सड़क छाप पत्रकार बनकर ऐसे शिक्षकों को हड़काने पहुंच जाते हैं।

शासन को स्वयं दैनिक मजदूरों जो शिक्षित प्रशिक्षित हो उनके लिए रुपए 150/- प्रतिदिन की मजदूरी भुगतान की दरें तय की है तो आखिर इन्हें वर्षों से रुपए 2500 में जोतकर चारों तरफ की परेशानियां लाद रखी है। फिर हड़काने, डराने, धमकाने के लिए सरपंचों से लेकर जिलाधीश, मुख्यकार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत तक सब ही तैयार बैठे रहते हैं। कभी निलंबन किया जाता , कभी कारण बताओ नोटिस जारी तिया जाते हैं।

इतनी सारी परेशानियां जिसमें सबसे बड़ी परेशानी मध्याह्न भोजन तैयार करवा कर ग्रामीण बच्चों को परोसने और खाना खिलाने की है। अब वह शिक्षक जहां चार होने चाहिए वहां दो ही हैं या एक ही शिक्षक है। कैसे तो सबको पढ़ाए और कैसे रुपए दो में खाने की व्यवस्था करे, फिर परीक्षा परिणाम बिगड़ता है या जांच में बच्चों या शिक्षास्तर निम्न होता है तो भी डांट-फटकार से लेकर कारण बताओ, निलंबन और नौकरी से हटाने की भी पीड़ा झेलना पड़ती है।

हाल ही में दीपावली के दिन भोपाल और छतरपुर में सैकड़ों संविदा शिक्षकों ने अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर न केवल प्रदेश स्तर पर भारी प्रदर्शन तो किया ही साथ ही भोपाल व छतरपुर में धरने, पर बैठे शिक्षकों ने अपने शरीर से खून निकालकर शासन में भ्रष्ट मोटीचमड़ी के सचिवों, प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस को अपनी पीड़ा दिखाने के लिए रक्त से दिए भी जलाए। परंतु इन निकम्मों को अपनी लूट खसोट और खोखली बयानबाजी से ही फुर्सत नहीं थी।

शासकीय कर्मचारियों को छठा वेतन मान भी दे दिया गया, बाद में महंगाई जैसी केंद्र ने भुगतान वह भी भुगतान करवा दी गई। हरामखोर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस इँडियन का इम प्रोटेक्शन सर्विस आदि की भारतीय स्तर की सेवाओं का वेतन न केवल कई गुना भुगतान कर रही है, म.प्र. सरकार इन सब लुटेरे भ्रष्ट शूकरों को देने के लिए पैसा है जो करोड़ों में भुगतान किया जा रहा है,फिर उन के लिए उनके घरों के लिए एक आई.ए.एस., आई.पी.एस. के पास न्यूनतम 10 दैनिक वेतन भोगियों से लेकर 25 से ज्यादा कर्मचारी, 2-4-5 वाहन चालक, 4-6 गाड़ियां इनकी सेवा में तैयार खड़ी रहती है। साथ ही लाखों में वेतन लेने के बाद रुपए 10 से 100 करोड़ रुपए प्रति माह भ्रष्टाचार से धन डकारने के लिए भी चाहिए,इन गिद्धों को।

इसके विपरीत संविदा शिक्षकों को दो वक्त के स्वयं के भोजन और रहन-सहन के लिए आने जानेके लिए भी धन नहीं है। शासन के पास ऐसे में यदि पुरुष शिक्षक हैं तो उनकी उम्र निकल जाती है कोई भी लड़की इन भिखारियों की तरह जिंदगी जीने वालों से शादी करना पसंद नहीं करती। महिला शिक्षिकाओं की तो फिर भी शादियां आसानी से हो जाती है। शादी के बाद ऐसी शिक्षिकाएं नौकरी छोड़ कर गृहस्थ बसा लेती हैं। परंतु पुरुष शिक्षकों की इतनी परेशानियां इतनी वेतन देखकर और सुनकर कोई पढ़ी-लिखी इस संबंध में सामान्य वर्ग वालों से बात भी करना पसंद नहीं करती।

रुपए 2500 के वेतनमें जानवरों का पेट नहीं भरा जा सकता, हर रोज फिर जीवन स्तर की बात तो दूर दो जोड़ी कपड़े खरीदने का नहीं सोच सकता। कहने को सरकारी नौकरी है मां-बाप का पेट भवने की तो दूर, फिर आए दिन कभी चुनाव ड्यूटी में चुनावी सर्वे, गरीबी रेखा के कार्ड में तहसील मुख्यालय जाता है तो कभी शासन के प्रधान सचिव, सचिव, मंत्री, आयुक्त, आदि शूकरों को इन 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को परेशानी नजर क्यों नहीं आती कि कम से कम उन्हें रुपपए 5हजार का वेतन तो दें। ताकि वो शिक्षक भले ही संविदा शिक्षक है कम से कम सिर उठाकर जी सके। अब यदि शिक्षक ही अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकता तो बच्चों से कैसे साफ सफाई के लिए कहेगा। पर वो बेचारा सिर झुकाए सरकारी नौकरी है के लालच में वर्षों नौकरी करता चला आ रहा है तो शासन में बैठे गिद्धों को उनका शोषण करने में भी शर्मिंदगी तो दूर उनकी समस्याएं न सुनकर ये भाजपा, जनता को क्या दिखाना चाहती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी संभागों को बंद करने का षड्यंत्र

राज्य के राज्यमार्गों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर भ्रष्टाचार का तांडव

भोपाल। मु.मं. शिवराज ने सारे भ्रष्ट पूर्व के मंत्रियों को अपने डकैतों के गिरोह में शामिल कर अपने ईमानदार होने का परिचय तो पहले ही प्रदेश और देश की जनता को दे ही दिया है। दूसरी ओर अपने मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेकर सभी विभाग प्रमुखों, सचिवों के पद पर उन्हीं धूर्त डकैतों, भ्रष्टों को ही बैठाया है जो उसको दोनों हाथ लूटकर भ्रष्टाचार से वसूली कर दे सके या दे रहे हैं, वहीं पदों पर शोभा बढ़ा रहे हैं। शिवराज की भी और विभाग की भी, चाहे वो जनसम्पर्क आयुक्त मनोज श्रीवास्तव हो या लोक निर्माण विभाग का सचिव और म.प्र. सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक महाधूर्त सुलेमान जिसने महानिकम्मे और भ्रष्ट अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुल्का को मुख्य अभियंताओं के रहने के बाद भी प्रमुख अभियंता का प्रभार सौंप म.,प्र. लोकनिर्माण विभाग को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के खुले तांडव का आह्वान किया है। इस चाल और विद्युत यांत्रिकीय के अधीक्षण यंत्री को प्रमुख अभियंता का प्रभार उस सौंप कर जिसे सिविल इंजीनियरिंग का ढंग से अ,ब,स,द भी नहीं आता, बना कर इस रबसर स्टाप को अपनी तरह से हांकने और खुली वसूली करने और पूरे निर्माण विभाग को भ्रष्टाचार के नाम ईमानदार अभियंताओं को भी बदनाम करने दबाव डालने जालसाजियां करने का कार्य चारों चरफ चल रहा है। यही कारण है कि पूरे लोक निर्माण विभाग में इंदौर संभाग के अभियंता महीने-महीने भर की छुट्टियों पर जाने लगे हैं। अब वे ही अभियंता जो महाभ्रष्ट, मक्कार, धूर्त है इस टीम में काम करना पसंद कर रहे हैं इंदौर ही लें तो मुख्य अभियंता का प्रभार महाभ्रष्ट रहे खंडवा का अधीक्षण यंत्री, सिंग इंदौर जोन का प्रभार संभाले है, दूसरा महाशैतान आर.एन. मिश्रा सहायक अभियंता संभाग का प्रभार संभाले है। ये वो शूकर है जो कदम दर कदम जालसाजियां तो करती ही हैं साथ ही अपने वरिष्ठों को परेशान करने, उन्हें नीचा दिखाने, मंत्री सचिव से मिलकर शिकायत करने, ठेकेदारों को भड़काने का इतिहास रहा है। इसी कारण वर्षों से जमे इस श्वान का स्थानांतरण तत्कालीन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा कर दिया था पर फिर भ्रष्टों को धन बांट कर इंदौर लौट आया और वर्षभर से वही पुराने ढर्रे पर लौट आया।

दूसरा संभाग दो जो शुरू से ही भ्रष्टों के हाथ में ही रहा, यहां का अभियंता ए.पी. राने, भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित करने इंदौर और ग्वालियर में करोड़ों की सम्पत्तियां खरीदने, हमेशा भ्रष्टाचार के लिए तीन तेरह नो अट्ठारह करने में लगा रहता है, पदस्थ है। पूर्व में इस शूकर सुलेमान ने मुख्य अभियंता कार्यालयों को बंद करने का षड़्यंत्र रचा था। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी प्रदेशभर के कार्यालयों को बंद करने की तैयारी पूरी चरम पर है। संभवतः 31/3/10 के बाद इन कार्यालयों में ताले डल जाएं और सारा स्टाफ भवन एवं पथ के उपखंडों, संभागीय अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता कार्यालयों में समापित कर दिया जाए। सुलेमान ने सारे राष्ट्रीय राजमार्गों से अधिकांश को छीन कर या तो म.प्र. सड़क विकास निगम के अधीन कर लिया है,या फिर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में चले गए हैं। दोनों का उद्देश्य पहले निर्माण में दो गुने, तिगुने लागत के बजट बना कर पहलो निर्माण में मोटी कमाई करना और ठेकेदारों को सौंप कर उन पर टोल वसूलना है, चाहे सड़क कैसी भी हो।

इंदौर-इच्छापुर मार्ग 203 किमी का हो ले तो इस पर 5वर्षों से टोल तो बराबर हर वर्ष बढ़ा कर वसूला जा रहा है, परंतु रखरखाव के नाम हर महीने वर्ष में किया जाने वाले पुननिर्माण का पता ही नहीं है। औरयहां बैठे इस निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. व्यास, इसके भी भ्रष्टाचार का राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वार्णिम इतिहास रहा है, उल्टे ही दावा करता है कि मैंने तो फिर भी अपने कार्यालय में 60 किमी का पुर्ननविनिकरण करवा ही दिया है।

वैसे भी इस धूर्त जालसाज ने सड़क विकास निगम में उन सारे भ्रष्टों की फौज बैठाई है जो पूर्व से ही कुख्यात श्रेणी के सफेदपोश डकैत रहे हैं। इंदौर-उज्जैन मार्ग को ही लें तो वराह की फौज ने जो सारी राजस्थान से आई है, चूंकि ये शूकरों की फौज रेगिस्तान से आईहै तो प्रदेश को भी जरूरत हो न हो हरे-भरे हजारों पेड़ काटकर बेच कर खा रही है और मार्ग के दोनों ओर की हरे-भरे वर्षों पुराने पेड़ काटकर रेगिस्तान बनाने पर तुली है। दूसरी ओर हजारों ट्रक मिट्टी, गिट्टी, कच्ची मुरम, पत्थर खोद कर सड़क पर तो बिछाई जा रही है परंतु करोड़ों रुपए के उत्खनन की सरकार को रायल्टी नहीं चुकाई गई है न इंदौर जिले में न उज्जैन जिले में,यही हाल पूरे प्रदेश का है। लगभग दो हजार कि.मी. से ज्यादा सड़कें बीओटी में बनाई गई, परंतु अधिकांश बीओटी ठेकेदारों ने रायल्टी नहीं चुकाई, जिसका पूरे प्रदेश के राजस्व में करोड़ों रुपए मिलता, दूसरी ओर बीओटी ठेकेदार सड़कें बनाने के लिए लाखों पेड़ काटकर बेचकर डकार रहे हैं। जबकि वो पेड़ शासकीय भूमि पर थे। सभी पेड़ों का वन विभाग के डिपों में जमा करवाया जाना चाहिए था, जिसका ठेकेदार और हजम कर गए, तीसरी तरफ सड़क बनाने से पूर्व निगम को वन विभाग को पेड़ों की कटाई से पूर्व सर्वे किया जाना चाहिए था वह भी नहीं किया गया था, न ही इसकी जानकारी लोक निर्माण के पास है। चौथा जब अनुबंध में किसी भी ठेकेदार को पेड़ काटकर लगाने की शर्त नहीं है तो उन डकैतों से ये उम्मीद करना, घोषणा करना पूर्णतः बेमानी है कि ठेकेदार दुगुना पेड़ लगाएगा। पूर्णतः जालसाजी का उत्कृष्ट नमूना है। सुलेमानी षड्यंत्रों का। इस उपरोक्त कहानी के सार में जो अगली कदम ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री कमलनाथ जो भ्रष्टों का सरगना रहा है ने जो रुपए 25000 करोड़ से सड़कों के निर्माण की घोषणा की है वे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग भी म.प्र. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभागों से छींन कर इस रा.रा. प्राधिकरण को सौंपे जाएंगे। स्वाभाविक है कि म.प्र. लोक निर्माण वि. के रा.रा. संभागों के पास सड़कें ही नहीं होंगी तो वो आसानीसे बंद कर दिए जाएंगे।चूंकि वे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग भी म.प्र. सड़क विकास निगम से लेकर बनाएगा अर्थात सुलेमान और मु.मं. रुपए 25000करोड का सीधा 30% अर्थात रुपए 7500 करोड़ डकार लेंगे। क्योंकि सारे प्राक्कलन दुगुने और तिगुने बनाए जाएंगे। जिसमें कमलनाथ का न्यूनतम रुपए 2500 करोड़ का हिस्सा होगा। इन सबका निष्कर्ष है कि अगले दो वर्ष बाद किसी भी राष्ट्रीयया राज्यों के मार्गों पर हर चौपीहिया वाहनों से सड़क पर चलने की भी वसूली होगी।

श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर
(म प्र. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा के अंतर्गत पंजीकृत)
सहकारी सप्ताह पर संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को
हार्दिक शुभकामनाएं
—पदाधिकारी—
—संचालकगण—
प्रबंधक : ... शाखा प्रबंधक : ...

व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लि., इन्दौर
महादेव शाहरा सभागृह, नई अनाज मंडी, संयोगितागंज, इन्दौर
फोन : 2477755-2477766, 4084827
सहकारिता सप्ताह पर हार्दिक अभिनंदन
गोपालदास अग्रवाल
अध्यक्ष
मोहनलाल सैनी — उपाध्यक्ष
महेन्द्रसिंह राजपाल — प्रबंधक
श्रीमती सीमा मंगल — उपाध्यक्ष
-संचालकगण-
श्री मनोज काला, श्रीमती किरण बागड़ी, श्री अरूणकुमार अग्रवाल, श्री सुकुमाल सेठी
श्री रामेश्वरलाल असावा, श्री प्रकाश व्होरा, श्री कमल अग्रवाल, श्री नंदकिशोर अग्रवाल
श्री सुरेश अग्रवाल, श्री गिरिराज गुप्ता, श्री हरि मंगल, श्री पुरूषोत्तम जिन्दल

सहकारिता सप्ताह के अवसर पर सभी सम्मानीय
सदस्यों-सहयोगियों एवं सहकारी मित्रों को
हार्दिक शुभकामनाएं..
हार्दिक बधाई...
सुकल्या ग्राम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
(पंजीयन क्रं. I.R.U.D.R. 296 दिनांक 02.05.1981)
भगवानसिंह बेलिया — अध्यक्ष
रमेश जैन
35/ए, दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुकल्या ग्राम, इन्दौर
फोन : 0731-2550133

पुराणों में वर्णित ८४ महादेव के १५, १६, १७, १८ मंदिर मोदी के कब्जे में

मंदिरों की भूमि पर कालोनी शॉपिंग माल की तैयारी

भ्रष्ट आयुक्त, भू-अभिलेख, जिलाधीश उज्जैन नाच रहे मोदी के इशारों पर

उज्जैन। भारतीय वेदों और पुराणों में वर्णित इस पवित्र तीर्थ नगरी में सहस्त्रों वर्षों से सैकड़ों मंदिरों की जमीनों पर वर्तमान में भू-माफियाओं, मंदिर से जुड़े पुजारियों का न केवल कब्जा है वरन इन हजारों वर्ष पुराने मंदिरों की भूमि के इस खेल में इन जालसाज भू-माफियाओं ने प्रशासन में बैठे जिलाधीश उज्जैन आयुक्त, नगर निगम उज्जैन, आयुक्त उज्जैन संभाग से लेकर प्रदेश के आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर तक में बैठे अधिकारियों, कर्मचारियों से ये हरामखोर धूर्त आयुक्त भी इस जालसाजियों में न केवल शामिल है, वरन् इन भू-माफियाओं से धन के बदले इन्हें संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

वेदों में वर्णित 84 महादेव मंदिर के 84/15 इन्द्रघुम्नेश्वर, 84/16 कलकलेश्वर महादेव, 84/17 अप्सरेश्वर महादेव, 84/18 इशानेश्वर महादेव मंदिर और इनसे जुड़ी जमीनों में सिंधिया राज्य के जमाने मेंरहा धूर्त मोहनलाल मोदी ने ये चारो मंदिर और इससे जुड़ी उस क्षेत्र की 50 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर न केवल अपनी पूरी कालोनी उज्जैन नगर के ठीक गोपाल मंदिर के पास वाले क्षेत्र में खड़ी कर रखी है। जानकारों के अनुसार सिंधिया के राज्य में उज्जान उसके अधिन था तब से जालसाद मोहनलाल मोदी उनका उज्जैन में मुनीम हुंआ करता था। जैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा हुआ उस धूर्त ने इन चारों मंदिरों और उनकी सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेकर वहां पूरा पान दरीबा से लगे क्षेत्र में कालोनी ही खड़ी कर दी और मोदी गली में भी 6-8 गलियां जहां पर पूरी बस्ती जिसका या तो वर्तमान में भी किराया वसूल रहे हैं। इसके खानदान में जालसाजों में हेमंत मोदी पिता मोहनलाल मोदी उम्र 65-70 वर्ष इसके बेटे किरण और पंकज और उनकी औलादों केप्रतीक मोदी आदि के नाम से इन धूर्तों ने जमीनें भी स्थानांतरित कर दी। चूंकि ये मंदिर सहस्त्रों वर्ष पुराने होने के साथ ही पौराणिक महत्व के हैं जिन्हें केंद्र शासन के पुरातत्व विभाग को अपने कब्जे में लेकर इनको अपने मूल स्वरूप में लाया जाना चाहिए था।

इसके विपरीत शासन में बैठे धूर्त, मक्कार, हरामखोरों और जालसाज जिलाधीशों जो आजादी के बाद से वर्तमान तक उज्जैन जिले में विराजे हैं। इस मोदी खानदान के टुकड़खोर श्वान बन इनके सामने दुम हिलाते नजर आते हैं। इस संबंध में सूचना के अधिकार में जो पत्र उज्जैन जिलाधीश को दिया गया था उसमें इस उज्जैन जिलाधीश कार्यालय के भ्रष्ट निकम्मों ने वह पत्र नगर निगम उज्जैन को भेज दिया, अर्थात् वही ढांक के तीन पात, दूसरी ओर आखिर जिलाधीश भू-अभिलेख और बंदोबस्त किस कार्य के लिए होता है इसके साथ ही एक पत्र 29/10/09 को आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को इन मंदिरों की वास्तविकता जानने के लिए ग्वालिय भेजा गया था जिसका जवाब पत्र क्रमांक 16/समन्वय/ लो.सू.अ./527/09 ग्वालियर से आवेदक को पृष्ठांकित करते हुए पुनः वहां कलेक्टर उज्जैन भू-अभिलेख को भेज दिया गया और आवेदक को जानकारी देने के लिए लिखा गया जिसका पृष्ठांकन क्रमांक 3241/16 समन्वय/ लोसूअ/ 527/09 ग्वालियर दिनांक 11/11/09 था।

अब इन भ्रष्ट श्वानों आयुक्त ग्वालियर और जिलाधीश उज्जैन की जालसाजियों की बानगी देखिए यही पत्र उज्जैन जिलाधीश को दिया गया वो उसने नगर निगम उज्जैन का अंतरित कर दिया, वही पत्र आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर को दिया गया। वह उसने जिलाधीश उज्जैन को अतंरित कर दिया जो स्पष्टतः इन हरामखोर की जालसाजियों का खुला दस्तावेज है। इन चारों मंदिरों 84/15,16,17,18 का रिकार्ड न केवल नगरनिगम उज्जैन, जिलाधीश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त उज्जैन और आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के पास तो है, साथ ही नगर निगम एवं ग्राम निवेश उज्जैन और भोपाल के पास होने के साथ ही म.प्र. पुरातत्व विभाग उज्जैन और भोपाल और केंद्रीय पुरातत्व एवं संग्रहालय इंदौर, भोपाल और दिल्ली के पास भी होगा।

पहले जिन तीन विभागों से जानकारी मांगी गई थी वहां इस मोदी खानदान के टुकड़ाखोर श्वानों की फौज बैठी है। स्वाभाविक है आवेदक ने यहां सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के लिए पत्र दिया और इन हरामखोर जालसाजों ने उस पत्र को कभी जोनों से जानकारी मिलेगी कहकर उलझा दिया। जबकि जानकारों के अनुसार इस मोदी खानदान के पास 100 से ज्यादा मकानों की सम्पत्ति अकेले मोदी गली में ही है। जिसका ये नगर निगम का भी संपत्ति कर नहीं चुका रहे न ही इसके किराए से मिलने वाली आय पर आयकर और किराये पर 12% सर्विस टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है, परंतु न तो नगर निगम उज्जैन, आयकर उज्जैन, न कस्टम एंड एक्साइज भी कोई कदम नहीं उठा पा रहा है।

अमेरिकी जिम्मेदार है...

पेज १ से जारी

दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में कहीं न कहीं आर्थिक, प्राकृतिक, औद्योगिक विकास दिखता है। इसलिए पहले षड्यंत्रकारी नीतियों के अंतर्गत वहां भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भूखमरी, शिशु मृत्युदर अविकसित कहने के बाद विश्व बैंक ऋण देकर वहां के शासन और प्रशासन पर अनावश्यक ऋण लादकर जो कि विकास के नाम, गरीबी मिटाओ, भूखमरी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देकर भ्रष्टाचार फैलाता है, उसके षड्यंत्रकारियों, अधिकारियों को ये अच्छी तरह मालूम है कि ऋण देकर पहले वहां शासन-प्रशासन के अधिकारियों को दिए ऋण से घी पीना सिखाओ तब ही अपने षड्यंत्रकारी और साम्राज्यवादी नीतियां सफल हो सकती हैं और पूरे एशियाई राष्ट्रों में चाहे वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईराक हो में शासन वहां के सत्ता नहीं वरन वाशिंगटन से चलता है।

भारत में उसने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक के माध्यम से हर प्रदेश की सरकारों के शासन और गरीबी दूर करने, स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक और सामाजिक संरचना के विकास के लिए भी विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से कर्जा लेकर तक केवल कागजों पर ही विकास दिखाकर 70 से 100% धन डकारने में भी नहीं हिचकते हैं। इस ऋण से जो विकास के नाम दिया जाता है और उसकी वसूली जनता पर लादे गए करों से की जाती है, शासन और प्रशासन में बैठे भ्रष्ट शूकरों, मंत्री, सचिव, अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसे धन से घी पी-पीकर इतने मुटिया जाते हैं, इन्हें राष्ट्र और राष्ट्र की जनता का हित तो दूर ये अपना वास्तविक हित मूल केवल जालसाजियों, भ्रष्टाचार से कमाई और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र व जनहितों की बर्बादी प तुले रहकर केवल अमेरिकी आकाओं के सामने दुम हिलाते नजर आते हैं, ये हाल हमारे मुखेरे श्वान, प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों जिनमें शरद पंवार, कमलनाथ, शशि थरूर, प्रणव, पी.चीट अंबरम तक पूरे कांग्रेसियों और इँडियन एव्यूसिंग लॉबी का है। अमेरिकी वर्ण शंकर इस प्रकार से केवल भारत को वरन पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जकार्ता, इंडोनेशिया जैसे विश्व के अनेकों देशों में 'कागज' के टुकड़े रूपी अमेरिकी डालर बांटकर सब उसके यहां बंधक बनाया हुआ है।

अमेरिकी वर्ण संकर कर्ज बांटकर अधिकांश एशियाई देशों को भारी भ्रष्ट बना चुके हैं, फिर हरामखोर एशियाई देशों विशेष कर पाकिस्तान और भारत की भ्रष्टाचार रेटिंग के शिगूफे पूरे विश्व के मीडिया में उछाल कर बदनाम करते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों से ये हरामखोर अमेरिकी मीडिया में कुछ जरूरत से ज्यादा कभी मानवाधिकार उल्लंघन, कभी भ्रष्टाचार में 37वां स्थान कभी 86वां स्थान, महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर हिंसा के आरोप लगाने से पहले दुनिया के सारे मानव प्रजाति के वर्ण संकर शूकरों एशियाई राष्ट्रों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांककर देखो, यदि हम भ्रष्ट हैं तो पिछले मात्र डेढ़ वर्ष में तुम्हारे की सौ से ज्यादा बड़ी-बड़ी बैंकों ने दुनियाभर क़े भ्रष्ट कर चोरों,यहां तक कि तुम्हारे देश मेंरहने वाले विदेयिों का पैसा डकार कर क्यों 150 से ज्यादा बैंक दीवालिया हो गए।

* अमेरिकी वर्ण संकरों, तुम्हारे यहां आबादी के हिसाब से कितने तलाक होते हैं, फिर हमारी आबादी से तुलना करो?

* अमेरिका में कुल आबादी के हिसाब से हर 1000 व्यक्तियों की आबादी में कितने अपराध होते हैं। उसके हिसाब से हमारी आबादी के अपराधों की संख्या देखो?

* हमारे यहां की 20% आबादी 1 वक्त भोजन करके भी तानकर सोती है और शांति प्रियता और चेहरे पर मुस्कुराहट पाई जाती है। उस हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी पेटु होते हैं, दुनिया के आम आदमी से 5 गुना ज्यादा चरते हैं। फिर भी दूसरे गरीब राष्ट्रों को उनकी आबादी को नोंचने से बाज नहीं आते।

* फिर भी हमें भ्रष्टाचार की रेटिंग देते हो।

* अपने हित साधने के लिए अपने कंडोम बेचने के लिए तुम मानसिक एड्स के मरीज हमारे देश के स्कूलों में यौन शिक्षा, परीक्षा खत्म करने जैसे यौन भ्रष्टाचार फैलाकर स्त्रियों की स्वच्छंदता की पैरवी करते व करवाते हो, ताकि तुम्हारे कंडोम बिकते रहे, हमारा देश कैसे भी बर्बाद और भ्रष्ट हो।

भ्रष्टाचार और आरक्षण...

पेज ८ से जारी

माओवादी हो, उल्फा हो, उनको मानसिक रूप से बगावत के लिए परिपक्व बना देता है। फिर वो हथियार उठाकर प्रशासन को उसके भ्रष्टाचार के कारण न केवल चुनौती देते हैं, थाने उड़ा देते हैं। रेलें रोक लेते हैं, स्टेशन उड़ा देते हैं और ऐसे पीड़ितों के नायक बन मसीहा बन जाते हैं।

मुख्यमंत्री चाहे शिव चौहान हो या रमन बैश उद्योगों को जमीन देते समय बिजली, पानी व अन्य सुविधायें स्थानीय जनता के अधिकारों को छीन कर देते समय तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, समृद्धि आएगी व अन्य ढेर सारे दिवा स्वप्नों की वर्षा कर दी जाती है, पर वास्तविकता में इसके विपरीत स्थानीय लोगों की जमीनें छीं कर समय पर न तो पूरी क्षतिपूर्ति दी जाती है न ही ये हरामखोर स्थानीय लोगों को ही रोजगार देते हैं। म.प्र. में ही देखें लगभग 25-30 बीओटी के सड़क के ठेकों में भी ठेकेदारों ने न केवल मजदूर, कुशल और अकुशल तक भी स्थानीय मजदूरों की अपेक्षा जहां का वो स्थायी निवासी था वहीं से लाया, अशोका बिल्डकान की इंदौर इच्छापुर मार्ग पर अधिकांश मजदूर, कर्मचारी महाराष्ट्र के हैं। इंदौर-उज्जैन की वाराह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी न केवल कुशल अकुशल श्रमिकों से लेकर मशीनें तक राजस्थानम की ही हैं। जबकि ये शूकरों का गिरोह इस सड़क के बहाने हजारों पेड़ों की आवश्यकता के विपरीत काटकर धड़ल्ले से बेच रहा है। जब समयमाया ने छापा इस तथ्य को तो उस श्वान सुलेमान ने घोषणा करवा दी 50 हजार पेड़ लगवाएंगे। इस जालसाज धूर्त सुलेमान से पूछो कि जो बीओटी ठेके 2003 से चल रहे हैं और रास्ते में पड़ने वाले जंगल काटकर जो बेच के खा गए, उन्होंने कितने पेड़ लगवा दिए पिछले 6 सालों में तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। इन हरामखोरों को तो पैसे दे दो, फिर कुछ भी करो।

यह सब भ्रष्टाचार धीरे-धीरे जब नक्सलवाद की शक्ल लेकर प्रशासन की व्यवस्थाओं को चुनौती देता है तो इनके पास केवल कोरी लफ्फाजी करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब जबकि हर तरफ 50% महिला आरक्षण, जातिगत आरक्षण के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। स्वाभाविक पढ़ा-लिखा युवा वर्ग रोजगार के अभाव में क्या करेगा, ऐसे संगठनों से जुड़कर वो अपनी प्रतिभा का विध्वंस उपयोग करेगा, आखिर जीने के लिए उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, बदले में तत्काल मिलने वाला नायकल, नाम और पैसा कमाने के लिए वह भी हथियार उठाकर अवैध वसूली, हिंसा का सहारा लेगा, बाद में जैसे वर्तमान में मुस्लिम आतंकवादियों यथा सिमी को स्थानीय लोगों से धन मिल रहा है। उल्फा को टाटा जैसी कंपनियां धन दे रही हैं। फिर बंबई से बंगाल, मिजोरम तक कश्मीर से केरल तक आखिर क्यों नक्सलवाद, माओवाद, उल्फा, मिजोरम न केवल विकसित, पल्लवित पोषित हो रहे हैं। कहीं- न कहीं प्रशासन शासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका मददगार रहा है, काश्मीर में ही आतंकवाद शासकीय धन से चल पल रहा है।

चीन के कर्मचारी नहीं, सब हैं जासूस

सुरक्षा पर भारी पड़ेगा चीनियों का भारत प्रवेश

मुक्त व्यापार की बर्बादियों का सत्ता में बैठे भ्रष्ट निकम्मे अय्याश कमीशन खोर कांग्रेसियों को भले ही अंदाज लगे न लगे पर सीधे परिणाम जनता के हर आमोखास के भुगतना पड़ रहे हैं। जहां राष्ट्र में उत्पादित अच्छा माल, कृषि उत्पाद आसानी से विदेशोंको निर्यात कर यहां महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, बदले में हमारे देश के नागरिकों का सड़ा गेहूं, दाल-चावल, शक्कर, तेल, सब्जियां और फूल, फ्रुट तक खाने पड़ रहे हैं। चाहे फिर वो चीनी दालों से लेकर मोबाइल भारी मशीनें हों या चीनियों की फर्मों द्वारा लगाए जा रहे पावर प्रोजेक्ट्स दुनिया जिस चीन और चीनी माल के नाम से रो रही है, वहीं हमारी सरकार आसन्न और भीषण खतरे को देखकर भी नजर अंदाज कर रही है। बेशक इन्हें जनता की न तो स्वयं की चिंता है न राष्ट्र की अपने स्वार्थ के लिए या राष्ट्र की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं। ये विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रित करने पर तुले हैं। बैंगलोर की आईटी फर्मों में जितने चीनी कर्मचारी आए उन्होंने काम जो किया सो किया पर भारत की सारी गोपनीय जानकारियां उन जालसाजों ने जासूसी कर चीन को अवश्य भेज दी और सारी गोपनीयता रखी रह गई। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे भारतीय जल, थल और वायुसेना के सुरक्षा के दसात्वेज इन सारी बातों को स्वयं भारत सरकार ने माना भी इसके विपरीत इन सावन के अंधों को अभी भी हरा -हरा ही दिख रहा है। क्या हमारी सरकार मेंदम है कि भारत से चीन जाने वालों को भी जासूसी का प्रशिक्षण देकर उनकी सारी गोपनीयता का वहां से हमारे कर्मचारियों के माध्यम से एकत्र कर लें।

जिस चीन से अमेरिका अंदर तक डरा हुआ है जो हमारी कांग्रेस सरकार के भाग्य विधाता है। उनके इशारे पर देश की सरकार चल रही है, अपनी जनता को रौंदने, नोंचने के लिए अमेरिका के इशारे पर कानून बना रही है। उस अमेरिका की औकात नहीं है कि वो चीन या चीनीयों के विरोध में कोई नीति बनाए या उनके माल को अमेरिका में आने से रोक दे। आजादी के बाद से चीन ने हमें हर कदम पटकनी ही दी है। इसके विपरीतहम अपने राष्ट्र के घरेलू उद्योगों को बर्बाद कर हम न केवल चीनी माल आयात कर रहे हैं, वरन चीनी मोबाइलों से देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने, आतंकी हमले करवाने की खुली छूट भी दे रहे हैं। भारत में निजी और संयुक्त उपक्रम कंपनियां जिन विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए चीनी कर्मियों और नागरिकों को भारत में बुलाने की बात कर रही है, उन्हें छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाल्को द्वारा बनाए जा रहे विद्युत उत्पादन केंद्र में सितम्बर 09 में गिरी चिमनी जिसमें 36 से ज्यादा श्रमिकों और इंजीनियर्स मारे गए थे, जिसमें रेत

बालकों की चिमनी से, चीनी माल और मानसिकता का अंदाज लगता है

की मात्रा ज्यादा मिलाए जाने से चिमनी बनाने से पहले ही धकस गई थी और सारे चीनी कर्मचारी दहशत में देश छोड़कर भागने के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे से पकड़े गए थे, से सबक ले लेना चाहिए।

ये हमारा और हमारे राष्ट्र की धरती का दुर्भाग्य ही है कि हम सब अपने स्वार्थों के लिए राष्ट्र को सबसे पीछे धकेलते आए हैं और हजारों वर्षों की गुलामी हमने हमारी पीढ़ीयों ने झेली है। इसके बाद भी अपने छोटे स्वार्थों की खातिर राष्ट्र को कभी सर्वोपरि न हम मानते हैं न हमारे कर्णधार नेता।

मोबाइलों के ए.एम.आई. नम्बर की बाच मार्च 09 से चलते-चलते नवम्बर 30 09 तक आ गई, पर चीनी मोबाइलों पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लग सका कि नेपाल, दिल्ली और मुम्बई से लेकर चीनी मोबाइलों से मिलने वाला मोटा लाभ न केवल व्यापारियों वरन उनसे ज्यादा जनता और उपभोक्ताओं का नजर आता है, भले ही वह हजारों का मोबाइल महीने, दो महीने भी न चले, दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक आयोग ने सुरक्षा कारणों से इन मोबाइल को प्रतिबंधित करने की कोशिश की तो चीनी मोबाइल के व्यापारियों ने बताते हैं कि चंदा कर एकमुश्त रुपए 50 करोड़ पहुंचा दिए, बात चलते-चलते नवम्बर 30 09 तक आ गई फिर पैसा पहुंच जाएगा तो 31/3/10 हो जाएगी। अगली तारीख यह एक छोटा सा नमूना है दुश्मन को सिर बैठाने और घर बुलाने का।

चीन का भारत द्वेष जगजाहिर होने के बाद भी न तो हमारे निकम्में सत्ताधीश कर्णधार चेतने को तैयार हैं न ही अन्य सरकारी कंपनियों से लेकर संयुक्त निजी कंपनियां और न ठेके वाली फर्में चाहे वो उद्योग लगाने की बात हो या माल बेचने., आईटी संस्थानों में नौकरी देने चीनी फर्मो द्वारा पावर प्रोजेक्ट लगानेका मामला हो, चीन तो चाहेगा कि अधिकतम चीनी कर्मचारी भारत में घुसे और अधिकतम जासूसी कर अधिक से अधिक भारतीय संस्थानों की जाननकारी एकत्रित करें। एक बार चीनी नागरिक भारत में घुसेगा तो वो सभी महत्वपूर्ण स्थानों, पुलों, पुलियों, बांधों, विद्युत केंद्रों,सुरक्षा संस्थानों, पुलिस, कानून, सैना, सैन्य गतिविधियों खदानों से लेकर क्षेत्रवार नागरिकों की मानसिकता तक का अध्ययन करेगा और जानकारी एकत्रित करेगा और करके के लगातार इंटरनेट के माध्यम से भेज रहाहमारी पुलिस की इतनी औकात नहीं कि वो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सके। उसे चुनाव करवाने, नेताओं, अधिकारियों, भ्रष्टाचार, महीना वसूली से तो फूर्सत मिलती नहीं वो बेचारी चीनी नागरिकों की जासूसी गतिविधियों पर क्या नजर रखेगी।

कार्य देवास जिलाधीश...

पेज 3 से जारी

में बैठे धूर्तों को आवेदक को राहत नहीं उन्हें अपनी जेब को राहत चाहिए इसलिए ये हर स्तर पर जालसाजियां कर रहे हैं।

*यदि ये ईमानदार होते तो पूरे प्रदेश के हर जिले के जिलाधीश से जो देवास जिलाधीश से पूछा गया है पूछते तो ईमानदारी झलकती और ईमानदार मानसिकता सामने आती।

* यहां बैठे धूर्तों ने पिछले 5 वर्षों में धारा 4 के 17 बिन्दुओं की जानकारी इंटरनेट साइटों पर डालने केक लिए प्रदेश के जिलाधीशों को कितनी बार निर्देशित किया, इनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं है।

* धारा 4 के 17 बिन्दुओं की जानकार को साइटों पर डालने के लिए न तो इन्होंने मुख्य सचिव से पूछा और कहा न ही सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव से पूछा और कहा। जो इनकी भ्रष्ट बीमार, बूढ़ी धूर्त वसूली की मानसिकता का स्पष्ट परिचय है।

* उल्टे ही देवास जिलाधीश के इस कार्य की प्रशंसा तो दूर, अपने हाथों से कमाई खिसकती देख उसे उलझाने की तैयारी है ये पत्र इसकी भाषा और तौर तरीका कि उन्होंने तो सामान्य प्रशासन का तो पत्र श्री अजमेरा को सौंप कर उनकी जालसाजियों को उजागर करवा दिया।

शासन को...

पेज 8 से जारी

प्रदूषण मंडल, औ.स्वा. एवं सुरक्षा जैसे वसूली कर तानकर सोते हैं

इन धूर्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी रेडियोधर्मी राख भोपाल गैस त्रासदी से ज्यादा खतरनाक और हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होगी। जो करोड़ों प्राणियों का हजारों वर्षों तक जीवन संकटमय बना देगी, पर हमारे केंद्र से लेकर राज्यों को कल की नहीं आज नोटों की चिंता है। घी पीने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड से ज्यादा घातक उद्योगों को बुला रहे हैं। दूसरी ओर ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश के कोने-कोने तक प्रदूषण फैलाने वालों से केवल महीना वसूली कर तान के सोते रहते हैं। यदि इंदौर को ही लें तो इंदौर नगर के ठीक बीचों बीच बने पोलोग्राउंड में इप्का जैसी फैक्ट्रियों जो छोटे से प्लांट को आजू-बाजू के उद्योगों को खरीद कर लगातार विस्तार कर रहे हैं। खतरनाक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। नालियों में रसायन बन रहा है, यही हाल सांवेर रोड की फैक्ट्रियों के हैं, वहां पर लगी रसायनों का उपयोग करने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से पूरे क्षेत्र का भू-जल प्रदूषित हो चुका है, परंतु सब वसूली कर तान कर सो रहे हैं। वैसे भी प्रदूषण नियंत्रण नहीं वह प्रदूषण फैलाए मंडल है। दूसरी ओर पीथमपुर में उसी यूनियन कार्बाइड के रसायनों जिसमें घातक गैस मिथाइल, आइसोसाइनायड, जिसे प्रदूषण मंडल अस्तित्वहीन मानता है का कुछ हिस्सा पीथमपुर के रामकी एन्वायरों में डंप किया जा चुका है, 1200 टन से ज्यादा रासायनिक कचरा और इकट्ठा

हो चुका है, जिसको जला कर भस्म करने के लिए 5वर्ष बाद भी भस्मक चालू नहीं हो सका है।

जैसा कि समयमाया ने सन 2004 में लिखा था कि यह कंपनी केवल बाइंड्रीवाल बना कर सीमेंट का गोडाउन बना देगी और रुपए 25 करोड़ के प्लांट में मिलने वाली रुपए 8 करोड़ के अनुदान का ही उपयोग करेगी, वही हो रहा है, उसने अनुदान में से भी रुपए 50 लाख से ज्यादा का काम नहीं कराया और रुपए 7.50 करोड़ हजम कर गई। कचरा इकट्ठा कर ताला लगाकर निकल लेगी और कचरा भेजने वालों से भी वसूली कर लेगी। सो वह वसूली तो दोनों हाथों कर रही है, पर कचरा निपटान के नाम पर वहां 5 वर्ष बाद भी भस्मक नहीं बना पाई है। इससे ही समयमाया के प्रस्तुत तथ्यों की सच्चाई स्पष्ट होती है। धार के प्रदूषण फैलाओ मंडल में बैठा त्रिवेदी और उसका स्टाफ भी वसूली कर पूरे पीथमपुर क्षेत्र में वही कर रहा है, वही हाल उज्जैन के उद्योगों का भी है। भोपाल में मंडीदीप में, मेलरोड जिसे रायसेन रोड भी कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र में भी वही सब कुछ हो रहा है, प्रदूषण के मामले में जो इंदौर का हाल है इन औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत में लागू भारतीय कारखाना अधि. 1948 में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए पूरा एक विभाग म.प्र. औद्योगिक स्वा. एवं सुरक्षा विभाग श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जो फैक्ट्रियां और प्लांट के डिजाइन से लेकर उसके कार्यशैली व श्रमिकों के स्वा. व. सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, यहां वर्षों से कुंडली मारे बैठे उप संचालकों, जिन्हें केवल वसूली और कागजी घोड़े दौड़ाने से मतलब है। इंदौर में बैठे कढ़िया को ही लें जो वर्षों से बैठकर केवल वसूली कर कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। ये दोनों ही विभाग उद्योगों की ऐसी त्रासदियों के लिए जिम्मेदार थे 25 वर्ष बाद भी दोनोंकी जिम्मेदारियों की दूर इन उद्योगों पर अंगुली तक नहीं उठी।

इस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जब सी.एन.एन. की साइट को देखा गया तो उन्होंने इस भीषण त्रासदी के दुष्परिणाम तो दिखाए परंतु जो तीन उन्होंने अपनी सफाई में पेश किए वो भी इनकी महान बत्तमीजियों का परिचय देते हैं। पहला प्लांट डो-जोन्स का नहीं था। दूसरा प्लांट का डिजाइन भी डो-जोन्स का नहीं था, तीसरा प्लांट के सेटअप में भारी बदलाव किया गया था। जालसाजों को सारी बातें 25 वर्ष बाद याद आ रही है। ताकि अमेरिकी, अमेरिकी कंपनियों और उद्योगपतियों के इतिहास में ये सब दर्ज हो भी जाए तो सफाई में तथ्य आखरी में लिखे जा सकें,उनकी और मरने वालों की कब्रों पर।

भ्रष्टों के इस देश में 2000 मरने वालों को जनता और मीडिया कह रहा है अनुमानित, मरने वालों भोपाल से तत्काल भाग कर अपने मूलस्थान पर जाने के बाद मरे उनका कोई अता-पता ही नहीं है। दूसरा इन 25वर्षों में कितने गैस पीड़ित मरे उसका भी कोई ठोस तथ्य नहीं है, परंतु सत्ताधीशों को जितने मरेंगे उतनी कमाई होगी।

करोड़ों खर्च...

पेज 4 से जारी

तो तुरंत संचालनालय को समर्पित करें। कार्यालयीन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बिल क्र. 169 दि. 20.3.2008 के हितराशि रुपए 42.900.00 का आहरण किया गया तथा आहरित राशि को निम्नानुसार वितरीत किया गया-

1. परियोजना अधिकारी पुनासा	14300.00	31.3.08
2. परियोजना अधिकारी हरसूद	14300.00	31.3.08
3. परियोजना अधिकारी कलडी	14300.00	31.3.08
योग	42900.00	

योजना के निर्देशों के अनुसार 3 0 हितग्राहियों को 3 बैचों में रुपए 14.300य00 प्रति बैंच के मान से रुपए 42,900.00 व्यय करना था। बाल विकास परियोजनाओं में अभी तक इस योजना के प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए। जिला कार्यालय की रोकड़ बही में परियोजना अधिकारियों को अग्रिम प्रदाय कर भुगतान पक्ष में अंतिम व्यय के रूप में दिखाया गया। जबकि वास्तव में राशि का उपयोग बिलकुल नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बजट आवंटन को लैप्स होनेसे बचाने हेतु उक्त राशि का आहरण किया गया था।

उत्तर में बताया गया कि योजना के अंतर्गत संचालनालय भोपाल से वर्ष 2007-08 का आवंटन मार्च माह के अंतिम दिनों में मिला था। प्रशिक्षण आयोजन हेतु दिनांक 31.3.08 को संबंधित परियोजना अधिकारियों को राशि दी गई। शीघ्रातिशीघ्र अग्रिमों का समायोजना किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण कार्य नहीं कराए गए और हितग्राहियों को लाभ नहीं पहुंचाया गया।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

बाल वैश्यावृत्ति...

पेज 8 से जारी

सैकड़ों कार्यक्रमों के बहाने नवयौवनाओं को घर से बाहर निकालकर यौनाचार करने में अपना शक्तिप्रदर्शन और महानता सिद्ध करने से नहीं चूकता। आखिर सरकार महिला बाल विकास प्रशासन, स्कूली शिक्षा विभाग, स्कूलों में बढ़ता बाल यौनाचार, बाल वैश्यावृत्ति पर टीवी, इंटरनेट साइटों पर बढ़ता और उससे बढ़ता यौनाचार क्योंनहीं रोकना चाहता?

सभी जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को शारदा एक्ट मनें बाल विवाहप से नैतिक अपराध लगता है और बाल वैश्यावृत्ति पर न केवल न्यायिक व्यवस्था, वरन हमारी विधायिका भी आंख मींच कर क्यों बैठी है। इससे ज्यादा बेहतर है कि बाल विवाह को कानूनी बना दिया जाए, ताकि स्कूली शिक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों में यौनाचार ही निरंकुशता न केवल बंद की जा सके, वरन् बाल विवाह से समाज में कम से कम नैतिकता तो बनी रहे, वैसे भी बाल विवाह में पिछड़ी जातियों में भी केवल विवाह का बंधन ही सामाजिक दृष्टिकोण से ही बांधा जाता है, गौना लड़की का जिसमें लड़की या वधु अपनी मां के घर से ससुराल 18 वर्ष की उम्र के बाद ही भेजी जाती है। तो बाल विवाह कम से कम अनैतिक और उच्छश्रृंखला यौनाचार को तो बढ़ावा नहीं देता, फिर बाल विवाह पर शासन-प्रशासन, पुलिस, महिला, बाल विखास के फोकट चंद क्यों इतना व्यर्थ का हल्ला मचाते हैं। जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र और उसकी साम्राज्यवादी विस्तार की अन्य सभी संस्थाओं का उद्देश्य ही खाया तो क्यों खाया, भ्रष्टाचार की श्रेणी में है नहीं खाया तो भूखमरी है, गरीबी है अनैतिक और गैर कानूनी है, उन हरामखोरों संकर के मानकों को तो नैतिक सामाजिक, आर्थिक रूप से विश्व के अन्य सभी देशों को नीचा दिखाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने का दुष्चक्र चलाना है। पूरी दुनिया उन हरामखोरों की जागीर नहीं जो जैसा चाहेंगे वो हांकेगे और भारतीय गुलाम उनकी हांक सुनेंगे।

भोपाल गैस त्रासदी

२५ वर्ष गुजर गए हम नहीं सुधरे

शासन को इंतजार है फिर मरे और फिर कमाएं

भोपाल गैस त्रासदी हमारे प्रदेश की राजधानी में बीच शहर में घटी विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, पर तब भी तात्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह धूर्त ने दोनों हाथों धन बटोरा और उनके साथ शासन में बैठे धुर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों से लेकर अदने से चपरासी ने भी दोनों हाथ वसूली की थी और वर्तमान में उसके धन में कुलांचे भर रहे हैं।

उस छोला रोड पर अभी भी विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, उस दुर्घटना से प्रभावित जो अभी भी जीवित हैं न तो शासन चिकित्सा सुविधाएं दिला पा रहा है, न ही उनके पुनर्वास की वर्तमान में भी ढंग से व्यवस्था की जा रही है, इससे बड़ा तिल-तिल जिंदगी जी रहे पीड़ितों का तो दुर्भाग्य है ही पर शासन में बैठे धूर्तों का बी ये दुर्भाग्य ही है कि विकास की लंबी चौड़ी गाथा गाने वाले औद्योगिक क्रांति का नारा लगाने वाले उसके दुष्परिणामों को नहीं समझ पा रहे हैं। नोटों के सावन में हुए अंधों को हर मौत के पीछे नोट नजर आ रहे हैं। इसलिए उससे ज्यादा खतरनाक परमाणु बिजली घरों को प्रदेश में और देश में बुला रहे हैं। अपने प्रदेश का कोयला और पानी दूसरों को बांट और अपने कोयले और पानी से बनी बिजली को बेच कृत्रिम संकट उपजा कर परमाणु घरों से बिजली केवल कमाई के लिए बनाना चाहते हैं। **शेष पेज 7 पर**

सरकारें पोषित कर रही नक्सलवाद

भ्रष्टाचार, आरक्षण कारण है नक्सलवाद के

फूट डालो, राज करो, हथियार बन चुके हैं नक्सली जालसाजों के

कांग्रेस अपनी 125वीं जयंती मनाएगी। ये वही कांग्रेस है जिसे दिसम्बर 1885 में अंग्रेज ए ओ ह्यूम ने स्थापित किया था। अंग्रेजों ने जिस रीति-नीति पर इस देश में 300 वर्ष राज किया जाते समय अंग्रेजों ने वनी विरासत 1947 में फूट डालो राज करो की रीति-नीति भारतीय कांग्रेसियों को सौंपी, अंग्रेजों ने तो अपनी महारानी के लिए देश से वसूली की और धन इंग्लैंड भेजा।

वर्तमान कांग्रेसी उस नीति पर चलकर स्वयं के लिए देश को बेच और गिरवी कर अपने लिए वसूल कर स्वीटजरलैंड भेज रहे हैं। देश बर्बाद हो, जनता चीखे चिल्लाए उनकी बला से। फिर वो जनता हथियार उठा ले, लूटपाट मारकाट और वसूली करे तो वो भी इनके लिए हथियार की तरह उपयोग में लेने लगे। स्व. विधायक बालाघाट लिखीराम कंवर को उनके ही लोगों ने निपटाया और नाम लगा दिया नक्सलियों का, जबकि उस विधायक ने बालाघाट की माइका, तांबे और अन्य खदानों की अवैध खुदाई आदि पर अपने ही मुख्यमंत्री से विवाद कर लिए थे। आखिर एक विधायक और मंत्री की हत्या उसी के घर में कर दी गईं और उसकी सुरक्षा में लगी पुलिस तान कर सोती रही, यह सिद्ध करता है कि नक्सलवाद सरकारों के लिए हथियार बन चुका है। पश्चिम बंगाल में भी लालगढ़ में 8 महीने से माओवादियों के कब्जे में थी तो, पश्चिम बंगाल की सरकार ने और प्रशासन ने क्या किया, वो तो उनको पाल रही है न कैसे कार्यवाही करेगी, राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे माओवादियों के कब्जे में रही बदले में पं. बंगाल सरकार ने दो महीने

बाद भी एक भी एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं करवाई।

देश में चीन का कितना दखल है और चीन को पं. बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार आंख मूंदकर कैसे और क्यों स्वीकार रही है, जबकि अधिकांश माओवादियों का चीन का न केवल समर्थन वरन् प्रशिक्षण तक चीन में दिया जाता है जो नेपाल के माध्यम से चीन पहुंचते हैं। यह बात उल्फा के आतंकियों ने सिद्ध कर दी जो न केवल आम आदमी भारत के साथ दुनिया का भी जानता है पर बेचारे भारत शासन में बैठे अय्याश हरामखोर, सत्ताधीश अधिकारी और मंत्री नहीं जानते। इन्हें 20 वर्ष बाद अब मालूम पड़ रहा है। जब इन माओवादियों के सफाई की बात उठती है तो पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार आखिर क्यों विरोध पर उतर आती है।

जहां तक कांग्रेसी गिरोह का जो केंद्र की सत्ता संभाल रहा है उसकी अय्याशियों, लूट, खसोट, कमीशन खोरी पर कोई भारतीय गुलाम अंगुली न उठाये वो कर रहे हैं, शान से करते रहें। जनता कभी हिन्दू-मुस्लिम में, कभी आतंकवादियों में, कभी नक्सली, कभी माओवादियों के हिंसा के तांडव नृत्य में उलझी दबी छुपी अपने जालमाल की रक्षा करती रहे।

अब पुनः अपने प्रदेश के और पड़ोस के छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सली तांडव की तरफ ध्यान दें तो वहां पर जाने के बाद मालूम चला कि वहां पर भी लूट खसोट और भ्रष्टाचार का चारों तरफ साम्राज्य है। जितनी भी कंपनियां चाहे वो विद्युत उत्पादन की नई इकायिों की निर्माण और स्थापना हो, लौह,तांबा, स्वर्ण, हीरा, क्रोमो जाइट का उत्खनन और विर्निमाण का मामला हो अधिकांश जिसमें जिंदल, स्टारलाइट, डी-मास, जैसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां है, वहां भी आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण कर उन्हें औने-पौने पैसे पकड़ा दिए जाते हैं। अधिकांश कंपनियां मजदूरों को बिहार, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश से पकड़कर या ठेका मजदूरों के सहारे बुलवा लेती हैं, उन्हें रुपए 50 से 100 रुपए रोज देती है। वहीं धीरे-धीरे जंगलों की सफाई कर बिहार, उ.प्र. के मजदूर अपनी झोपड़ियां बना कर रहने लगते हैं। बाद में शाम होते ही शराब पीकर अड़ोस पड़ोस की आदिवासी लड़कियों और औरतों को उठा लाते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं। ज्यादा चिल्ला-चोट मचाने पर हत्याएं तक कर दी जाती हैं। पुलिस उद्योगपतियों के इशारे पर नाच कर सारे मामले रफा-दफा कर दिए जाते हैं। यहीहाल छत्तीसगढ़ के हर जिले का है। बाद में वो ही आदिवासी बदले की भावना से नक्सलियों से मिलकर ऐसे बदला लाते हैं। साथ में ऐसी शिकार महिलाओं का आक्रोश आदिवासी महिलाओं को भी हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देता है। जहां तर प्रशासन, पुलिस का सवाल है तो चाहे फिर वो म.प्र. हो, छ.ग., उ.प्र.या पूरा देश यहां तक कि केंद्र सरकार सब ही उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की रखैल होते हैं। उन्हें जनता और कानूनों से ही नहीं उन्हें अपनी कमाई से मतलब होता है। यह भ्रष्टाचार का तांडव ही चाहे वो नक्सली हो **शेष पेज 6 पर**

यूरोप चाहता है हमारे यहां यौन उच्छृंखलता फैले

बाल वैश्यावृत्ति चलेगी, बाल विवाह नहीं

स्कूली लड़कियों में फैल रहा यौनाचार से धन कमाना

यूरोप विशेषतौर पर अमेरिका, इग्लैण्ड, फ्रांस, कनाडा आदि में सहशिक्षा में फैला, स्वच्छंद यौनाचार से वहां 12 से 16 लड़कियां स्वच्छंद यौनाचार में किसकी मां बन जाती हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनकी कोख में और गोद में पल रहे बच्चे का बाप उनका कौनसा दोस्त, शिक्षक, घरेलू नौकर, ड्राइवर है। यूरोप चाहता है वैसा ही यौनाचार भारत में फैले, ताकि परिवारवाद समाप्त हो जाए। वैसे ही अपराध हो भारत में भी जैसे यूरोप में हो रहे हैं।

भारत में जिस बाल विवाह के ऊपर विश्वस्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यू.एन.ओ. व यू.एन.ओ. के अन्य सभी संगठन जो अमेरिकी साम्राज्यवाद फैलाने और विश्व के दूसरे राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाने, उनका ये संगठन नैतिक सामाजिक, आर्थिक, पतन की ओर धकेलने के लिए कार्य करते हैं। बाल विवाह को लेकर ये सभी जालसाज भारी आलोचनाएं करते हैं और पिछले 60वर्ष से करतके चले आ रहे हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि हमारे यहां का मीडिया दृश्य, श्रव्य और मुद्रित इन हरामखोर जालसाज यूएनओ और उनके अन्य जालसाज संगठनों की हर रिपोर्टस को आंख मींच कर भारत में बड़ा ही चढ़ा कर छापते और महान समझते हैं। वही हालहमारी भारत सरकार का भी है। वह भी उनकी छापी हर रिपोर्ट उनके खरीदे हुए गुलामों की तरह अक्षरशः मान लेती है। बिना उसके पीछे चली जा चालों और जालसाजियों को समझे, इसके

परिणाम हमारे सामने है।

इंदौर के स्कूल की 15-16 वर्ष की लड़की स्कूल ड्रेस में जाने के लिए घर से निकलकर सीधे हवाई अड्डे पहुंच कर रायपुर के लिए फुर्र हो जाती है, वहां उसके ग्राहकों को खुश करती है और स्कूल ड्रेस में ही घर लौट आती है। जब वह लड़की रुपए 10,000 खर्च करके रायपुर आ जा रही है तो कितना कमा रही होगी।

14-15 साल की तीन लड़कियां स्कूल जाते समय बातें करती जा रही थीं कि रात में मैं उस गली से गुजर रही थी तो दोनों लड़के वहां खड़े हुए मुझे इशारा करके बुलाया, मैंने देखा कोई नहीं है तो मैं उसके पास गई तो साले डरकर दोनों भाग गए, मैंने बुलाया तो आने को तैयार नहीं हुए, क्लास में बहुत उचकता था, मैंने उससे बोला, बोल कहां ले चलेगा, तो डर गया, साले ने बात करना ही छोड़ दिया।

टीवी पर 24 घंटे बंटता यौनाचार समाचार पत्र-पत्रिकाओं में छपती यौनाचार उत्तेजकतापूर्ण समाचार, फिल्मी वैश्याओं की नग्न तस्वीरें इंटरनेट पर चलती हजारों नग्न साइटें इस देश की नारी को जो स्वच्छंद और उन्मुक्त यौनाचार की ओर घसीट रही है। राष्ट्र की संस्कृति परिवार वाद को तार-तार बिखेर रही है। टीवी पर 24 घंटे सुरक्षित यौंनाचार के लिए कंडोम, माला डी, 72घंटे के विज्ञापन हमारी युवा होती पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं। अब भारत सहशिक्षा में पढ़ने वाली षोडषियां 80% 16वर्ष की होने से पहले ही यौनाचार का आनंद उठा चुकी होती है। अकेले इंदौर में ही 18 से कम उम्र की लड़कियां हजारों में विशुद्ध यौनाचार के धंधे से कमाई में लगी है। अब माताएं शादी की बाद नहीं अपनी युवा होती बेटी से कमाई और उसके यौवन को हथियार बनाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने लगी है।यह बात पूरे देश के बड़े शहरों से लेकर राष्ट्र के गांवों तक इन टीवी मीडिया वालों ने फैला दी है और सरकार स्वास्थ्य संगठन महिला बाल विकास, स्वयं सेवी संस्थाएं और उनके कर्ताधर्ता अपनी फोटो अखबारों में छपवाने अपनी प्रशंसा करवाने बाल विवाह रोकने तो पहुंच जाते हैं और बाल विवाह करवाने वालों और करने वालों पर वधु के माता-पिता का पुलिस में प्रकरण दर्ज करवा कर अपनी महानता सिद्ध करते है। सारा मीडिया भी सियारों की तरह हुंआ-हुंआ करने लगता है। पर यही मीडिया के सियार गरबों के बहाने, तंबोलाव अन्य **शेष पेज 7 पर**

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से

प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.

कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803